www.dhyeyaias.com

अगस्त 2020 | अंक 01

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 भारत में वर्षा जल संचयन
आवश्यकता एवं चुनौतियाँ

2 मातृ मृत्यु दर में कमी : सुधार की ओर बढ़ते कदम

3 भारत में कुपोषितों की संख्या में गिरावट : उम्मीद की किरण

4 भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी : समय की मांग

5 भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन : पुनर्जीवन की आवश्यकता

6 चाबहार परियोजना का भविष्य और भारत

7 वैश्विक जनसंख्या में वर्तमान प्रवृत्ति

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

अगस्त 2020 | अंक 01

ध्येय IAS
most trusted since 2003

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–15

- भारत में वर्षा जल संचयन : आवश्यकता एवं चुनौतियाँ
- मातृ मृत्यु दर में कमी : सुधार की ओर बढ़ते कदम
- भारत में कुपोषितों की संख्या में गिरावट : उम्मीद की किरण
- भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी : समय की मांग
- भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन : पुनर्जीवन की आवश्यकता
- चाबहार परियोजना का भविष्य और भारत
- वैश्विक जनसंख्या में वर्तमान प्रवृत्ति

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 16–22

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 23–24

7 महत्वपूर्ण खबरें 25–29

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 30

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 31

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 32

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 भारत में वर्षा जल संचयन : आवश्यकता एवं चुनौतियाँ

संदर्भ

- मॉनसून के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ का संकट आ जाता है लेकिन मौसम बीतते ही अधिकांश हिस्से पानी की किल्लत से परेशान होते नजर आएंगे। जलसंकट से पूरा देश परेशान है। ऐसे में पानी बचाने के लिए बारिश का मौसम मुफीद है। रेनवॉटर हार्वेस्टिंग (rain water harvesting) ऐसी ही एक तकनीक है।

परिचय

- पृथ्वी का लगभग 71 फीसदी हिस्से पर पानी ही है। इसके अलावा 1.6 फीसदी पानी जमीन के नीचे है। यानि इतना सब होने पर भी सबसे मुश्किल वस्तु है पानी। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97 फीसदी महासागरों में है, जोकि नमकीन होने के कारण पीने योग्य नहीं है। मात्र 3 फीसदी पानी ही पीने योग्य है जिसमें से 2.4 फीसदी पानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ग्लेशियरों में जमा हुआ है। कमोवेश यह भी पीने के लिए सुलभ नहीं है। अब बचता है मात्र 0.6 फीसदी पानी। वहीं जिसे पीने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जोकि नदियों, झीलों और तालाबों में है।
- इसके अलावा जमीन के नीचे मौजूद 1.6 फीसदी पानी के भण्डार में से भी पीने हेतु पानी निकाला जाता है। इसके बाद भी गर्मियों के मौसम में प्रायः देश के अधिकांश हिस्सों में सूखे जैसे हालत हो जाते हैं। इसलिए जानकार मानते हैं कि जब पानी बरसे तो इसी पानी को बचाने पर हमारा सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। साथ ही घरों से व्यर्थ निकलने वाला पानी भी हम पृथ्वी के अन्दर सुरक्षित कर आने वाले कल के लिए बेहतर जीवन की कल्पना कर सकते हैं।

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता क्यों

- भारत में करोड़ों लोग शहरों में रहते हैं और इन शहरों में पानी की मांग बहुत ज्यादा है। शहरी प्रशासन अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था के तहत इस मांग के ज्यादातर हिस्से को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, अभी भी तमाम शहरों के बहुत से ऐसे इलाके हैं, जहां पर जल आपूर्ति की सरकारी सेवाएं नहीं पहुंच सकी हैं।
- इन समस्याओं की उत्पत्ति के पीछे कई कारण हैं। इसमें नगर निगमों के पास नागरिकों को आपूर्ति के लिए उपलब्ध पानी की तादाद में कमी भी शामिल है। इसके अलावा शहरों के जल प्रबंधन की कमियां भी ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार हैं। इसीलिए देश के तमाम नगर निगम अब शहरों में पानी की आपूर्ति बेहतर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो अलग अलग स्रोतों, जैसे कि नदियां, झीलें, नहरें, भूगर्भ जल और बारिश के पानी को जमा करके शहर वासियों को ज्यादा पानी उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं।

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं उसका महत्व

- बारिश के पानी को कुछ खास तरीकों से इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षाजल संग्रहण या रेनवॉटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसकी मदद से जमीन के भीतर के पानी का स्तर बढ़ जाता है। ये तकनीक पूरी दुनिया में अपनाई जा रही है। ये प्रणाली उन सारी जगहों पर इस्तेमाल हो सकती है, जहां हर साल न्यूनतम 200 मिलीमीटर बारिश होती है। इससे भविष्य के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। जिन इलाकों में धरती पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं उपलब्ध है कि उसे पाइप के जरिए सप्लाई किया जा सके। वहां पर बारिश के पानी को जमा करने के सिस्टम की उचित व्यवस्था करके, तमाम समुदायों की पानी की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं।
- बारिश के पानी को जमा करने के फायदों को देखते हुए, भारत के बहुत से शहरों के प्रशासन बारिश के पानी को इकट्ठा करने के विचार को लोकप्रिय बनाने और इस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि, निजी और सरकारी इमारतों, मकानों और हाउसिंग सोसाइटी, संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर वर्षा जल के संचयन की सुविधा स्थापित की जा सके।
- उदाहरण के लिए दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए तीन सौ से अधिक कुएं बनाए गए हैं। इनसे भूगर्भ जल के खजाने को फिर से बेहतर बनाया जाता है। चूंकि, दिल्ली हवाई अड्डे पर पानी का उपयोग बहुत अधिक (45 लाख लीटर प्रतिदिन/उसक) है। इसलिए, बारिश के पानी को जमा करके, और उपयोग किए जा चुके पानी को रिसाइकिल करके, हवाई अड्डे के अधिकारी पानी की इस भारी मांग को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके एयरपोर्ट, पहले से ही भारी मांग के बोझ तले दबी दिल्ली शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव कम करने में भी सहयोग करता है।
- जिन इलाकों में भूमिगत जल मीठा होता है, वहां हार्वेस्टिंग के लिए रिचार्ज का तरीका अपना सकते हैं। इसके तहत रेनवॉटर हार्वेस्टिंग फिल्टर के जरिए बारिश के पानी को सीधे गड्ढे तक पहुंचाते हैं। इससे साफ पानी का स्तर बढ़ता है। छत के आकार के

हिसाब से फिल्टर की कीमत अलग-अलग होती है, जो 3000 से लेकर 10000 तक भी हो सकती है।

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए भारत सरकार के प्रयास

- शहरी विकास पर संसदीय समिति ने साल 2015 में पेश अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की था कि केंद्र सरकार के सभी कार्यालय और रिहायशी भवनों पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाना चाहिए। समिति ने यह भी कहा था कि इससे संबंधित अपडेटेड आंकड़ा तैयार किया जाए। इससे पहले 2013 में जारी रिपोर्ट में भी समिति ने यही सिफारिश की थी।
- नीति आयोग के अनुसार, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को जल संरक्षण और भूजल को रिचार्ज करने का एक सरल, व्यवहारिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीका माना जाता है। ऐसे में देश के कई राज्यों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बना दिया गया है। शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक प्रति 100 स्क्वायर मीटर क्षेत्र की छत से हर साल 55,000 लीटर तक जल का संरक्षण किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में 140 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल पर निर्मित होने वाले सभी भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बना दिया गया है।
- इसी प्रकार राजस्थान में सभी सरकारी भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में भी नई इमारतों में कानूनन, रेनवाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बना दिया गया है। कर्नाटक में रेनवाटर हार्वेस्टिंग करवाने पर सम्पत्ति कर में 5 वर्ष तक के लिये 20 प्रतिशत की छूट मिलती है।

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग से जुड़ी चुनौतियाँ

- बारिश का पानी काफी हद तक साफ होता है, लेकिन अगर वातावरण में प्रदूषण है, तो वर्षा जल के भी प्रदूषित होने का खतरा रहता है। अगर बारिश के पानी को ठीक तरीके से इकट्ठा और जमा नहीं किया गया, तो भी इसके प्रदूषित होने का खतरा रहता है। इस वजह से कई चुनौतियां उठ खड़ी होती हैं। भारत के शहरों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहता है और इस बात की पूरी आशंका होती है कि इस प्रदूषण का बारिश के पानी पर भी बुरा प्रभाव पड़े। इसी तरह, इमारतों की छतें, या जहां बरसात का पानी जमा होता है। जैसे कि, गड्ढे या खाली जमीन। वो जगहें भी धूल, चिड़ियों की गंदगी, कीड़ों और कचरे की शिकार होती हैं। अगर, इन अशुद्धियों को पाइप, पानी जमा करने के टैंक या गड्ढों में जाने से नहीं रोका जाता, तो पानी की गुणवत्ता तो खराब हो ही जाती है, और गड्ढे या टैंक भी तलछट से भरने का खतरा रहता है।
- इकट्ठा किए गए बारिश के पानी में जिंक या सीसे की मिलावट भी हो जाती है। इसका कारण छतों पर लगी धातुओं, पाइप या टैंक से रिसाव होता है। अगर ऐसी अशुद्धियों वाला पानी पीने में इस्तेमाल होता है, तो सेहत की गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कहना है कि, 'बारिश की पहली बौछार में आमतौर पर कीटाणु ज्यादा पाए जाते हैं और जैसे-जैसे आगे बारिश होती है, तो उसमें प्रदूषण की मात्रा कम होती जाती है। वहीं पानी जमा करने के लिए बने टैंक अगर खुले हैं, तो वहां मच्छरों की भारी आबादी जमा हो जाती है।
- बारिश के पानी में इन खनिजों जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है। इनकी कमी से पानी का स्वाद भी अलग हो जाता है। बिना खनिज मिलाए, ये पानी पीना भी इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

आगे की राह

- पानी के प्रदूषित होने के खतरे को कम करना, कितना पानी जमा करना है, उसकी योजना बनाना, पत्तियों और कचरे को फिल्टर करना, पहली बारिश के पानी को किसी और दिशा में मोड़ने की व्यवस्था करना, टैंकों को ढकना, तूफान के पानी को टैंक में घुसने से रोकना, टैंक में जमा पानी का उचित प्रबधन और तलछट जमा होने से रोकने के लिए फिल्टर की व्यवस्था। साथ ही साथ टैंक में जमा पानी का स्तर नियमित रूप से जांचना और पानी का उचित इस्तेमाल सुनिश्चित करना जरूरी है।
- सरकार को प्रयास करना चाहिए कि नागरिकों को बारिश के पानी को जमा करने से होने वाले आर्थिक और पर्यावरण के फायदों के प्रति और जागरूक करे साथ ही घनी आबादी वाले इलाकों की ऊंची इमारतों, जैसे कि बहुमंजिला बिल्डिंग, हाउसिंग सोसाइटी, संस्थानों की इमारतें और कारोबारी बिल्डिगों में बारिश का पानी जमा करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं उसके महत्व का वर्णन करें साथ ही उससे जुड़ी चुनौतियों पर भी प्रकाश डालें।

02 मातृ मृत्यु दर में कमी : सुधार की ओर बढ़ते कदम

चर्चा का कारण

- हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) के मामले में भारत द्वारा प्राप्त सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की मातृ मृत्यु दर में 1 वर्ष में 9 अंकों की गिरावट देखी गई है।
- देश में एमएमआर में 2011 से लेकर 2018 के दौरान लगातार कमी देखी जा रही है। 2011-2013 में जहां इसका अनुपात 167 था वहीं 2014-2016 में यह 130 हो गया, 2015-17 में यह घटकर 122 और 2016-18 में 113 रह गया है। इस प्रगति के फलस्वरूप यह उम्मीद की जा रही है कि भारत सतत विकास लक्ष्यों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में जल्द ही सफल हो सकता है।

क्या है मातृ मृत्यु दर?

- मातृ मृत्यु दर, गर्भावस्था के दौरान या शिशु के जन्म के समय माँ की मृत्यु के दर को कहा जाता है। मातृ मृत्यु दर महिला एवं बाल स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों और संस्कृतियों में मातृ मृत्यु के भिन्न-भिन्न कारण हैं तथा इसका प्रभाव विभिन्न देशों/प्रदेशों के मातृ मृत्यु दरों में झलकता है। भारत में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों तथा महिला जनसांख्यिकीय स्तर पर भी इन दरों में सार्थक भिन्नता है।

सुरक्षित मातृत्व की जटिलता के कारक

- अशिक्षा, जानकारी की कमी, समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, कुपोषण, कच्ची उम्र में विवाह, बिना तैयारी के गर्भधारण आदि कुछ कारणों की वजह से माँ बनने का खूबसूरत अहसास कई महिलाओं के लिए जानलेवा और जोखिम भरा साबित होता है। कई मामलों में माँ या नवजात शिशु या दोनों की ही मौत हो जाती है।
- ज्यादातर मातृ मृत्यु की वजह बच्चे को जन्म देते वक्त अत्यधिक रक्त स्राव के कारण होती है। इसके अलावा इंफेक्शन, असुरक्षित गर्भपात या ब्लड प्रेशर भी अहम वजहें हैं। प्रसव के दौरान लगभग 30 प्रतिशत महिलाओं को आपात सहायता की आवश्यकता होती है।
- गर्भावस्था से जुड़ी दिक्कतों के बारे में सही जानकारी न होने तथा समय पर मेडिकल सुविधाओं के ना मिलने या फिर बिना डॉक्टर की मदद के प्रसव कराने के कारण भी मौतें हो जाती हैं।
- जच्चा और बच्चा की सेहत को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का अहम रोल होता है लेकिन इनकी कमी से कई महिलाएं प्रसव पूर्व न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाती हैं। समस्त मातृ मौतों में से लगभग 10 प्रतिशत मौतें गर्भपात से संबंधित जटिलताओं के कारण भी होती हैं।

भारत की स्थिति

- वर्तमान में भारत में प्रति वर्ष लगभग 2,000 मातृ मृत्यु की कमी हुई है, जो भारत के लिए अच्छी खबर है। यह सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इस तरह भारत 2030 तक 70/ लाख जीवित बच्चों के जन्म के सतत विकास लक्ष्य और 100/ लाख जीवित बच्चों के जन्म की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) लक्ष्य 2020 को हासिल करने की राह पर अग्रसर होता दिख रहा है।
- एसडीजी लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या अब 3 से बढ़कर 5 हो गई है। इन राज्यों में केरल (43), महाराष्ट्र (46) तमिलनाडु (60), तेलंगाना (63) और आंध्र प्रदेश (65) शामिल हैं।
- ध्यातव्य है कि देश में ग्यारह राज्य हैं जिन्होंने एनएचपी द्वारा निर्धारित एमएमआर के लक्ष्य को प्राप्त किया है, जिसमें उपरोक्त 5 के अलावा झारखंड (71), गुजरात (75), हरियाणा (91), कर्नाटक (92), पश्चिम बंगाल (98) और उत्तराखंड (99) जैसे राज्य हैं।

- इसके अलावा तीन राज्यों पंजाब (129), बिहार (149), ओडिशा (150) में एमएमआर 100-150 के बीच है, जबकि 5 राज्यों छत्तीसगढ़ (159), राजस्थान (164), मध्य प्रदेश के लिए (173), उत्तर प्रदेश (197) और असम (215), एमएमआर 150 से ऊपर हैं।
- इस वर्ष राजस्थान में मातृ मृत्यु दर में 22 अंको की अधिकतम गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ उत्तर प्रदेश में 19 अंकों, ओडिशा में 18 अंकों, बिहार में 16 अंकों और मध्य प्रदेश में 15 अंको की गिरावट दर्ज हुई है।

सतत विकास लक्ष्य और मातृ मृत्यु दर

- पर्यावरणीय उपेक्षा न करते हुए संधारणीय विकास द्वारा मानव की प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 17 सतत विकास लक्ष्यों को 169 प्रयोजनों के साथ स्वीकार कर 2030 तक इन्हें वैश्विक स्तर पर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित हुआ था।
- इन्ही लक्ष्यों में 2030 तक मातृ मृत्यु दर को 70 (प्रति 1 लाख जीवित बच्चे) करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मातृ स्वास्थ्य में सुधार डब्ल्यूएचओ की प्रमुख प्राथमिकताओं में से भी एक है।
- डब्ल्यूएचओ शोध प्रमाणों को बढ़ाकर, साक्ष्य-आधारित नैदानिक और प्रोग्राम संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करके, वैश्विक मानकों को निर्धारित करने और प्रभावी नीति और कार्यक्रमों को विकसित करने और लागू करने के लिए सदस्य राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करके मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में योगदान देता है।

सरकारी प्रयास

- संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के साथ-साथ सेवाओं की गुणवत्ता और उनकी पहुंच पर ध्यान केन्द्रित करने के सरकार द्वारा किये गये गहन प्रयास ने सफलता की तरफ मार्ग प्रशस्त किये है।
- इसके अलावा सेवाओं की गुणवत्ता और कवरेज पर ध्यान देकर सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के माध्यम से गिरावट में प्रमुख योगदान दिया है।
- सरकार ने प्रसव के उपरांत तथा प्रसव पूर्व की देखभाल के लिए मिड वाइफ की व्यवस्था करने के साथ ही सुमन कार्यक्रम को लागू करने की भी योजना बनाई है ताकि प्रसूताओं और नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की व्यापक पहुंच हो सके।

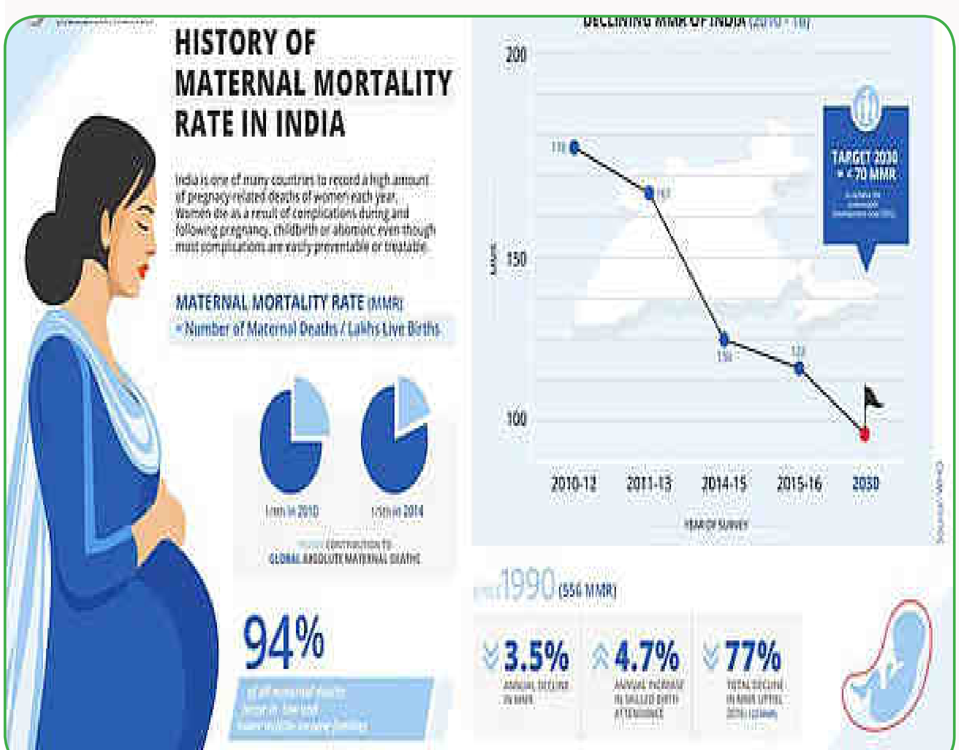

- इसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के कार्यान्वयन और अंतर-क्षेत्रीय कार्रवाई ने सबसे अधिक हाशिए और कमजोर आबादी तक पहुंचने में मदद की है।
- एमएमआर को कम करने में निरंतर प्रगति से देश को 2030 तक 70 से नीचे एमएमआर के एसडीजी 3 लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

सरकार द्वारा किये गये अन्य प्रयास

- सरकार द्वारा किये गये कुछ अन्य पहलें जिसमें LaQshya, (लक्ष्य) मिशन पोषण अभियान, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि भी शामिल है जिससे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी।

लक्ष्य मिशन (LaQshya)

- भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसूति गृह और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए "लक्ष्य" (Labour room Quality improvement Initiative-LaQshya) पहल की शुरूआत की।
- यह प्रसव-पूर्व और तत्काल प्रसवोत्तर अवधि पर केंद्रित एक बहुआयामी दृष्टिकोण है। इसमें प्रसूति गृह और प्रसूति ऑपरेशन थियेटर में प्रसव के दौरान, मातृत्व और नवजात मृत्यु दर तथा रुग्णता को कम करना और सम्मानजनक मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करना शामिल है।

पोषण अभियान

- पोषण अभियान को मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू में लॉन्च किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य, गर्भवती महिलाओं, माताओं व बच्चों के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अतिरिक्त इसका लक्ष्य बच्चों, महिलाओं में खून की कमी (एनीमिया) को दूर करना भी है।
- यह महिला व बाल विकास मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम आँगनवाड़ी सेवा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना

योजना, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा से जुड़ा है।

जननी सुरक्षा योजना

- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। इसे गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृत्व एवं नवजात मृत्यु दर घटाने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इस योजना की शुरुआत 12 अप्रैल, 2005 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। यह योजना कम निष्पादन वाले राज्यों (एलपीएस) पर विशेष बल के साथ सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है।
- जेएसवाई एक 100% केन्द्र प्रायोजित योजना है। यह योजना गर्भावस्था के दौरान प्रसूति पूर्व देखभाल, प्रसव के दौरान संस्थागत देखभाल तथा प्रसूति उपरांत देखभाल के साथ-साथ नकद सहायता भी प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

- इस अभियान की शुरुआत जून 2016 में हुई थी और इसका सकारात्मक असर अब दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इस अभियान का आह्वान किया था। इस अभियान के तहत मातृत्व मृत्यु दर को प्रति एक लाख जीवित जन्म पर 13 तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
- यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की पहल है जिसके तहत हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित की गई है। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी प्रेग्नेंसी के चौथे महीने के बाद प्रसव पूर्व देखभाल से जुड़ा हेल्थ केयरिंग पैकेज दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक मातृत्व लाभ की योजना है जिसका आरम्भ 2010 में इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से (IGMSY) हुआ था। इस योजना के अंतर्गत पहले बच्चे के जन्म के लिए 19 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नकद राशि दी जाती है। इस राशि से बच्चा होने और उसकी देखभाल करने के कारण दिहाड़ी मजदूरी में हुई क्षति का सामना करने वाली महिला को आंशिक क्षतिपूर्ति दी जाती है और साथ ही इससे सुरक्षित प्रसव और उत्तम पोषण का प्रबंध किया जाता है।

आगे की राह

- मातृत्व मृत्यु दर कम करने हेतु एक अच्छी तरह से प्रबंधित प्रणाली की आवश्यकता है जो गर्भवती महिलाओं को न्यूनतम जोखिम के साथ मातृ स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करे, साथ ही विनियामक और कानूनी प्रावधानों के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ कार्य भी साझा करे।
- हाल के वर्षों में देश ने अनेक सूचकांकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रगति की है और देश में नवजात शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर), कुल प्रजनन दर (टीएफआर) जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकेतकों में पर्याप्त प्रगति की है।
- अभी भी इस ओर कई कार्य किए जाने की आवश्यकता है और महिलाओं को प्रसव के दौरान बचाने की मुहिम के समक्ष कई चुनौतियाँ भी हैं। जिनमें किशोरियों को यौन शिक्षा और स्वच्छता, शारीरिक विकास के लिए सही पोषण, गर्भनिरोधक उपायों की आसानी से उपलब्धता और समुचित जानकारी प्रमुख हैं। इसके साथ ही पूरे देश में, खासकर ग्रामीण इलाकों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराए बगैर लक्ष्य को पाना संभव नहीं है।
- महत्वपूर्ण रूप से, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को COVID-19 लक्षणों, रोकथाम और स्वच्छता पर गर्भवती महिलाओं से संबंधित जोखिम, कलंक और संवेदीकरण को कम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. भारत में मातृ मृत्यु के कारण और उसे कम करने हेतु उपायों की चर्चा करें।

03 भारत में कुपोषितों की संख्या में गिरावट : उम्मीद की किरण

संदर्भ

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले एक दशक के दौरान कुपोषित लोगों की संख्या में 60.7% की गिरावट आई है, जो 2004-06 में 21.7 प्रतिशत से घटकर 2017-19 में 14 प्रतिशत हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बच्चों में बौनेपन और हकलाने की समस्या कम हो गई है, परन्तु अब देश में वयस्कों में मोटापा (ओबेसिटी) एक समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है।
- इसके अलावा विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में करीब 69 करोड़ लोग कुपोषित हैं यह संख्या 2018 के मुकाबले एक करोड़ ज्यादा है।

परिचय

- ध्यातव्य है कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएडी), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है।
- इस रिपोर्ट में भूख और कुपोषण को खत्म करने की दिशा में हुई प्रगति पर नजर रखते हुए भारत के परिपेक्ष में कहा गया कि भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 2004-09 में 249.4 मिलियन से घटकर 2017-19 में 189.2 मिलियन हो गई।
- रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी और दक्षिण एशियाई देश जो इस प्रगति को प्रदर्शित कर रहे हैं,उनमें चीन और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। इन देशों की परिस्थितियों, इतिहास और आर्थिक प्रगति की दर में पर्याप्त भिन्नता है। इसके बावजूद, लंबी अवधि के आर्थिक विकास, असमानता में कमी और बुनियादी वस्तुओं व सेवाओं तक बेहतर पहुंच के कारण इन देशों ने भुखमरी को कम करने में सफलता पाई है।

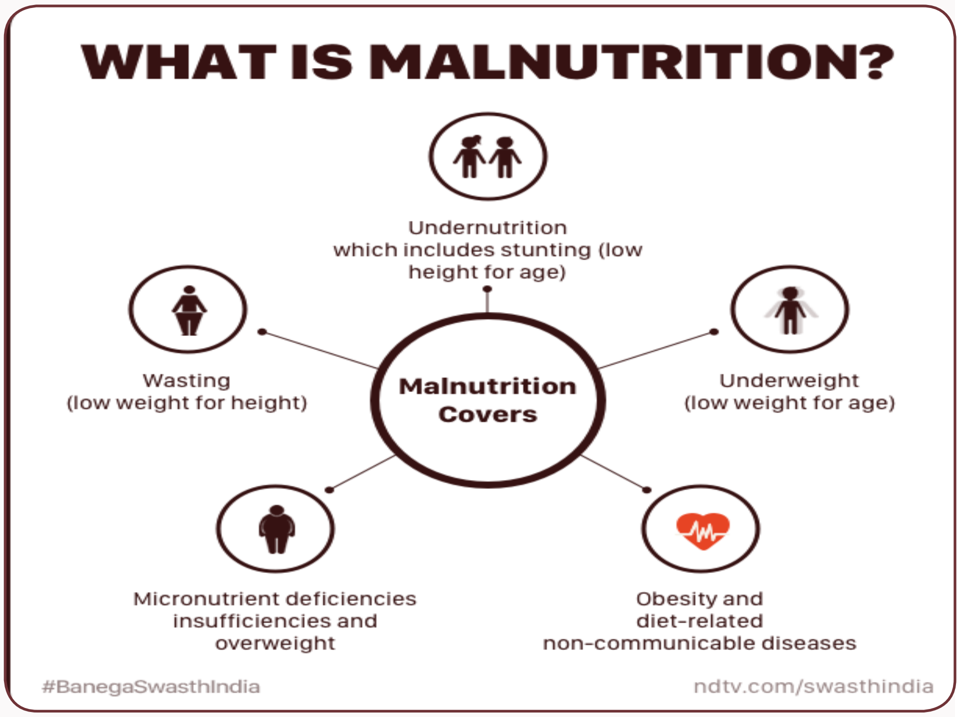

कुपोषण

- शरीर के लिए आवश्यक सन्तुलित आहार लम्बे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं।
- कुपोषण प्रायः पर्याप्त सन्तुलित अहार के अभाव में होता है। बच्चों और स्त्रियों के अधिकांश रोगों की जड़ में कुपोषण ही होता है।
- स्त्रियों में रक्ताल्पता या घेंघा रोग अथवा बच्चों में सूखा रोग या रतौंधी और यहाँ तक की अंधत्व भी कुपोषण के ही दुष्परिणाम हैं।
- इसके अलावा ऐसे अनेक रोग हैं जिनका कारण अपर्याप्त या असन्तुलित भोजन होता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में तकरीबन 690 मिलियन लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा, और यह संख्या वर्ष 2018 से 10 मिलियन ज्यादा है।
- एनीमिया से प्रभावित किशोरियों और महिलाओं (15-49) की संख्या 2012 में 165.6 मिलियन से बढ़कर 2016 में 175.6 मिलियन हो गई।
- 0-5 महीने के कुपोषित शिशुओं विशेष रूप से स्तनपान करने वालों की संख्या 2012 में 11.2 मिलियन से बढ़कर 2019 में 13.9 मिलियन हो गई।
- रिपोर्ट ने माना है कि एशिया में कुपोषितों की संख्या सबसे अधिक है, परन्तु अफ्रीका में इसका विस्तार सबसे तेजी से हो रहा है। यदि हम आँकड़ों पर गौर करें तो पायेंगे कि एशिया में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक लगभग 381 मिलियन है, वहीं दूसरे स्थान पर अफ्रीका है जहाँ कुपोषितों की कुल संख्या 250 मिलियन है और इनकी तादाद तेजी से बढ़ रही है।
- इस बीच, वयस्कों में मोटापा भी अपने आप में एक वैश्विक महामारी बनता जा रहा है। ताजा अनुमान यह है कि तीन अरब या उससे अधिक लोग एक स्वस्थ आहार नहीं ले रहे है या लेने में असमर्थ है।
- रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि विश्व स्तर पर अपने सभी रूपों में कुपोषण

का यह बोझ विश्व के सभी देशों के लिये एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। जिसपर हमारे सरकारों और संगठनों को तात्कालिक कार्य करने की आवश्यकता है।

भारत की स्थिति

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में भी विस्तार से आकलन किया गया है, उसमें से कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं –
    - भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की प्रवृत्ति 2012 में 47.8% से घटकर 2019 में 34.7% अर्थात 2012 में 62 मिलियन से घटकर 2019 में 40.3 मिलियन हो गई।
    - इसके अलावा 5.6 प्रतिशत (38.3 मिलियन) बच्चे अत्यधिक वजन की समस्या का सामना कर रहे थे।
    - 2012-16 के बीच भारतीय वयस्कों में मोटापा बढ़ गया है। 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यस्क जो मोटे हैं उनकी संख्या 2012 में 25.2 मिलियन से बढ़कर 2016 में 34.3 मिलियन हो गई।

नकद हस्तांतरण कार्यक्रम

- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आमतौर पर नकद हस्तांतरण कार्यक्रम को अच्छी तरह से जुड़े शहरी या ग्रामीण संदर्भों में आहार विविधता बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त साधन माना जाता है। इस तरह के स्थानान्तरण दूरदराज के क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं,जहां बाजारों तक पहुंच गंभीर रूप से सीमित है।
- इस संदर्भ में भारत में, ग्रामीण व्यवसाय केंद्रों ने छोटे किसानों को तेजी से बढ़ते शहरी बाजारों से जोड़ने की सुविधा प्रदान की है जो कि एक कृषि हब के रूप में काम करेगा। किसानों से खाद्य उत्पादों की खरीद के अलावा, ये हब कृषि आदानों और उपकरणों जैसी सेवाओं के साथ-साथ ऋण तक पहुंच प्रदान करते हैं।
- एक ही स्थान पर खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और शीतलन की सुविधा होने से उपभोक्ताओं को ढेर सारी अर्थव्यवस्थाओं से लाभान्वित होने में मदद मिलती है और पूरे खाद्य आपूर्ति शृंखला में लेनदेन की लागत कम हो जाती है। भारत में इस मॉडल ने ग्रामीण सुपर मार्केट को जन्म दिया है, जो सस्ता भोजन उपलब्ध कराते हैं।
- गौरतलब है कि इस व्यवस्था के अलावा भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी दुनिया में सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करती है, जो 800 मिलियन लोगों तक सब्सिडी वाले अनाज पहुंचाती है, जिसे देश भर में 500,000 से अधिक की दुकानों से उचित मूल्य खरीदा जा सकता है।

COVID-19 का प्रभाव

- रिपोर्ट के पूर्वानुमान के अनुसार COVID-19 महामारी के कारण 2020 के अंत तक 130 मिलियन से अधिक लोग भुखमरी का सामना कर सकते है।
- प्रतिशत के लिहाज से अगर गौर करें तो अफ्रीका इसके लिए सबसे अधिक प्रभावी क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में यहां 19.1% लोग कुपोषित हैं। वर्तमान रुझानों को देखा जाये तो हम कह सकते हैं कि 2030 तक अफ्रीका, दुनिया की आधी से अधिक भूख से पीड़ित और कुपोषित लोगों का आवास होगा।
- COVID-19 के कारण स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के कारण सबसे कमजोर आबादी समूहों की पोषण स्थिति और अधिक खराब होने की संभावना है।
- रिपोर्ट का अनुमान है कि COVID-19 महामारी के पश्चात् आर्थिक विकास परिदृश्य के आधार पर वर्ष 2020 में विश्व में कुल कुपोषित लोगों की संख्या में 83 मिलियन से 132 मिलियन तक की वृद्धि हो सकती है।
- COVID-19 खाद्य पदार्थो के उत्पादन, वितरण और उपभोग को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों और प्रक्रियाओं के रूप में समझी जाने वाली वैश्विक खाद्य प्रणालियों की कमजोरियों और अपर्याप्तताओं को उजागर कर रहा है।
- COVID-19 महामारी का वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर काफी अधिक प्रभाव पड़ा है और इसके कारण वैश्विक खाद्य प्रणाली काफी कमजोर हो गई है।

आगे की राह

- इस अध्ययन के द्वारा सरकारों से अपील की गयी है कि वे अपने देश में विकास के दृष्टिकोण में मुख्यधारा के पोषण हेतु भोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और विपणन में लागत-वृद्धि कारकों में कटौती करें, जिसमें अक्षमताओं, भोजन की बर्बादी और कचरे को कम करना (प्रबंधन) भी शामिल है।
- इसके अलावा सरकारों को भी अपने स्थानीय लघु-स्तरीय उत्पादकों को समर्थन देने और अधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थ बेचने और बाजारों में उनकी पहुंच को सुरक्षित रखने और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में पोषण और निवेश रणनीतियों में परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहिए।
- इसके साथ ही देश में बच्चों की पोषण स्थिति को प्राथमिकता देने और शिक्षा तथा संचार के माध्यम से उनके व्यवहार में बदलाव लाने की भी आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

Topic:

- गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे।

प्र. कोविड-19 महामारी का वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे आप कितना सहमत है? चर्चा करें।

04 भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी : समय की मांग

संदर्भ

- हाल ही में 2013 से निलंबित किए गए एक मुक्त व्यापार समझौते पर हुई वार्ता को पुनर्जीवित करने की एक नई पहल के रूप में भारत और यूरोपीय संघ के पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते (बीटीआईए) को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने हेतु एक "उच्च स्तरीय बातचीत" की घोषणा की।
- इस शिखर बैठक में भारत और यूरोपीय संघ ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल में सहयोग समझौते से लेकर दूरगामी महत्व के सामरिक साझेदारी हेतु 2025 तक का रोडमैप बताने वाला एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें रक्षा और सैन्य सहयोग का दायरा बढ़ाना, समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए वार्ता प्रक्रिया स्थापित करना, सुरक्षा मसलों पर नियमित संवाद स्थापित करना, भारतीय और यूरोपीय नौसेना के बीच आपसी सहयोग बेहतर करने के लिए सहयोग और आदान-प्रदान आदि शामिल हैं।
- भारत-यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ से आने वाले निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2017 में स्थापित निवेश सुविधा तंत्र (आईएफएम) का बेहतर उपयोग करने के लिए भी सहमत हुए।

पृष्ठभूमि

- 27 सदस्य देशों का यूरोपीय संघ अपने भारी आर्थिक विकास के अनुरूप वैश्विक स्तर पर समुचित राजनीतिक भूमिका नहीं निभा पा रहा था, परन्तु अब ब्रिटेन के यूरोपियन संघ से अलग हो जाने के बाद संघ ने विश्व के राजनयिक क्षेत्रों में अपनी हलचल कुछ बढ़ाई है और इसका इरादा भविष्य में और सक्रिय भूमिका निभाने की है। इसी संदर्भ में भारत ने भी यूरोपीय संघ के साथ तीन साल बाद विगत 15 जुलाई को 15वीं शिखर बैठक की जरूरत महसूस की।
- गौरतलब है कि यूरोपीय संघ में तीन देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सबसे प्रभावशाली रहे हैं, इसलिए वैश्विक मामलों के बारे में तीनों में आम राय और एकजुटता जरूरी थी, पर ब्रिटेन द्वारा अलग राग अलापने की वजह से साझा नीति नहीं बन पा रही थी।
- अलबत्ता वैश्विक मामलों में यूरोपीय संघ कभी प्रभावशाली आवाज नहीं बन सका, इसलिए भारतीय सामरिक हलकों में यूरोपीय संघ के साथ रिश्तों को उतनी अहमियत नहीं दी गई। यूरोपीय संघ भी भारत के प्रति अब तक इसलिए उदासीन रहा कि भारत ने मुक्त व्यापार संधि और निवेश संरक्षण संधि को हरी झंडी नहीं दी थी, पर चीन के खिलाफ यूरोप में जिस तरह भावनाएं प्रबल होने लगी हैं, वैसे में, भारत के लिए यह सुनहरा मौका है कि यूरोपीय कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने की दिशा में कदम उठाया जाए।
- 15 वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में घोषणाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, रणनीतिक साझेदारी के उद्देश्यों का गठन है, जो अगले पांच वर्षों में भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों को निर्देशित करने के लिए तैयार किया गया है।

यूरोपीय संघ के बारे में

- यूरोपीय संघ एक आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में काम करता है। इनमें से 19 देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं जबकि अन्य 9 यूरोपीय संघ के सदस्य (बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम) यूरो का उपयोग नहीं करते हैं।
- यूरोपीय संघ का यूरोपीय देशों के बीच सदियों से चली आ रही युद्ध की समाप्ति के लिए एक एकल यूरोपीय राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा से विकास किया गया था, जिसका समापन द्वितीय विश्व युद्ध के साथ शुरू हुआ और इसका अधिकांश भाग समाप्त हो गया।
- यूरोपीय संघ ने कानून के एक मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार विकसित किया है, जो सभी सदस्य राज्यों पर लागू होता है, जहां सदस्य एक साथ कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं।

भारत और यूरोपीय यूनियन

- यूरोपीय संघ और भारत में रणनीतिक,वैचारिक और आर्थिक समानता पिछले कुछ वर्षों से पुनः दृष्टिगोचार हो रही है। उदाहारणस्वरुप दोनों का उद्देश्य रणनीतिक स्वायत्तता और उनकी वैश्विक स्थिति को बढावा देना है। रणनीतिक मूल्यशृंखलाओं में विविधता लाना भी एक सामान्य हित में शामिल है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों का निवारण करना भी आवश्यक है और यूरोपीय संघ और भारत इन प्रयासों में एक-दूसरे का समर्थन कर सकते हैं।
- गौरतलब है कि दोनों पक्षों के बीच 2000 में सामरिक साझेदारी का रिश्ता स्थापित हुआ, फिर नियमित तौर पर सालाना शिखर बैठकें होती रहीं, पर हाल में उदासीनता के कारण शिखर बैठकें नहीं हुई, फिर भी 20 साल में दोनों के बीच 15 शिखर बैठकें हो चुकी हैं।
- वर्तमान में एक सौ अरब यूरो के द्विपक्षीय व्यापार के साथ यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार बन चुका है और अंतरिक्ष से लेकर विज्ञान-तकनीक के कई क्षेत्रों में दोनों के बीच गहरा सहयोग रहा है। साथ ही यह द्विपक्षीय व्यापार कुछ हद तक भारत के पक्ष में है।

यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार

- विशुद्ध रूप से आर्थिक शर्तों पर, यूरोपीय संघ भारत का पहला व्यापारिक साझेदार है और 2018 में किए गए 67.7 बिलियन यूरो निवेश के साथ सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जो कुल एफडीआई प्रवाह के 22% के बराबर है। परन्तु सुधार की गुंजाइश अभी भी है, खासकर जब चीन में यूरोपीय संघ के निवेश की तुलना में, जो उसी वर्ष (2018) में 175.3 बिलियन यूरो था।

- उन्नत व्यापारिक सहयोग यूरोपीय संघ और भारत दोनों को अपने रणनीतिक मूल्य शृंखलाओं में विविधता लाने और चीन पर आर्थिक निर्भरता को कम करने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं।
- आपसी समझ को बेहतर बनाने और नवाचार और विकास के अवसर पैदा करने के लिए लोगों की गतिशीलता और कनेक्टिविटी को सुगम बनाना भी दोनों देशों के लिए बेहतरीन तरीका है।

यूरोपीय संघ और भारत के बीच FTA पर समझौता

- यूरोपीय संसद के एक नए अध्ययन में यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार समझौते के संभावित प्रभाव का आकलन किया गया है जिसके अनुसार दोनों पक्षों के लिए 8 बिलियन यूरो से 8.5 बिलियन यूरो के व्यापार में वृद्धि हुई है, साथ ही व्यापार के अधिक वृद्धि से भारत में प्रवाह की संभावना है।
- यह अध्ययन पर्यावरणीय मानकों जैसे वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान पर अतिरिक्त समन्वय से संभावित लाभ को भी संदर्भित करता है।
- जलवायु परिवर्तन पर, यूरोपीय संघ अपने नए औद्योगिक रणनीति ग्रीन डील के माध्यम से 2050 तक कार्बन-उत्सर्जन को तटस्थ बनाने के लिए अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर निर्माण कार्य कर रहा है।

भारत के लिए अवसर

- यूरोपीय लोग भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि प्रदान करने में भारत की अहम भूमिका स्वीकार करते हैं। वे प्रौद्योगिकियों और भविष्य के मुद्दों पर एक साथ काम करने में काफी संभावनाएं देखते हैं।
- परन्तु भारत COVID-19 के बाद यूरोप के लिए एकमात्र आर्थिक विकल्प नहीं है इसलिए, भारत को यूरोपियन स्थानांतरण कंपनियों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित सुझावों पर अमल करना चाहिए :
    - ब्रॉड-आधारित व्यापार और निवेश समझौते को वापस ट्रैक पर लाना होगा।
    - एक नए निवेश समझौते को शामिल करते हुए, हमें 5 जी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उच्च-प्रौद्योगिकी सहयोग में शामिल होना होगा।
    - इसके अलावा यूरोप को भी व्यापार पर अपनी स्थिति को बदलने और सेवाओं पर भारत को समायोजित करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी।

COVID-19 के कारण उभरी परिस्थितियाँ

- COVID-19 के कारण उत्पन्न हुए संकट को यूरोपीय संघ के लिए अवसर माना गया है, ताकि इसकी कीमत साबित हो सके। इस संदर्भ में यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तुत "अगली पीढ़ी के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव" ने अपने साहसिक दृष्टिकोण से कई लोगों को आश्चर्यचकित किया है।
- इसने वास्तव में एक गेम-चेंजर का कम किया है जो न केवल इसके वित्तीय निहितार्थ में है, जिससे यूरोपीय संघ को कर्ज लेने की अनुमति देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि यूरोपीय संघ को बांधने वाले संबंध किसी संधियों और व्यक्तिगत सदस्यों के स्वार्थ से परे है।

निष्कर्ष

- यूरोपीय संघ के विकास की जड़ें विभाजित यूरोप के एकीकरण की तलाश में हैं, क्योंकि यहाँ लंबे समय तक अत्यधिक राष्ट्रवाद की वजह से विश्व युद्ध भी हुए हैं। हालाँकि समूह के कमजोर सदस्यों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में यूरोपियन यूनियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के साथ बहुपक्षीय संस्थानों के सतत सुधार को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ और भारत को भी सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहिए।
- परन्तु अब सवाल यह है कि क्या यूरोपीय संघ और भारत वर्ष 2050 तक कार्बन-तटस्थ अर्थव्यवस्थाओं में बदलने में सफल हो सकते हैं और क्या यह निवेश दोनों पक्षों को लाभान्वित कर सकता है। इसलिए, एक मजबूत साझेदारी यूरोपीय संघ और भारत दोनों को वैश्विक निर्णय लेने में मदद करेगी।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और समृद्धि के अपार अवसर हैं। उल्लेख करें।

05 भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन : पुनर्जीवन की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुट निरपेक्ष (Non&Aligned Movement & NAM) देशों के वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन कोरोना वायरस के वैश्विक संक्रमण से उपजे खतरे को लेकर आयोजित हुआ था। गुट निरपेक्ष देशों का यह सम्मेलन अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव की कोशिशों के बाद आयोजित किया गया। इल्हाम अलियेव गुट निरपेक्ष आंदोलन के मौजूदा चेयरमैन हैं।

परिचय

- गुट-निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने निरंतर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि यह आंदोलन सहयोग और रचनात्मक कार्यकलापों के आधार पर आगे बढ़े। अप्रैल 1955 में जब गुट-निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो तत्कालीन संस्थापक नेताओं का उद्देश्य यह था कि किसी भी एक देश का पक्ष लेने की बजाय विकासशील और अविकसित देशों को एक मंच पर लाया जाए।
- गुट-निरपेक्ष आंदोलन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप ब्रॉज टीटो ने शुरू किया था। गौरतलब है कि दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद दुनिया अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ (अब रूस) के नेतृत्व तले दो गुटों में बंट गई थी। अमेरिका वाला खेमा पूंजीवादी नीतियों का पोषक और समर्थक माना जाता था तो सोवियत संघ का खेमा समाजवादी नीतियों को मानने वाला था। उस समय दुनिया के कई देश आजाद हुए थे और अपने विकास और दूसरे देशों के साथ संबंधों के लिए नीति निर्धारण कर रहे थे। इन देशों ने तय किया कि वे किसी एक गुट में शामिल होकर दूसरे गुट के विरोध में खड़े होने की बजाए गुट निरपेक्ष रहेंगे ताकि उनके संबंध किसी से खराब न हों। इस आंदोलन में एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देश शामिल थे।
- 1961 में इस आंदोलन की स्थापना के बाद गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, क्षेत्रीय एकता एवं सुरक्षा को साम्राज्यवाद, जातिवाद, रंगभेद एवं विदेशी आक्रमण, सैन्य हमले, हस्तक्षेप आदि मामलों के विरुद्ध उनके युद्ध के दौरान सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही किसी पावर ब्लॉक के पक्ष या विरोध में ना होकर निष्पक्ष रहना है।

कोविड 19 के दौर में गुटनिरपेक्ष देश

- गुटनिरपेक्ष देशों के 18 सम्मेलन हुए हैं, जिनमें आखिरी अजरबेजन के राष्ट्रपति इलहाम अलीव की अध्यक्षता में 28-29 अक्टूबर 2019 को बाकू में हुआ था। इस सम्मेलन में समसामयिक विश्व की चुनौतियों का संगठित एवं पर्याप्त उत्तर सुनिश्चित करने के लिए बांदुंग सिद्धांतों को बरकरार रखने पर जोर दिया गया। वास्तव में दुनिया बहुत बदल चुकी है और समय के साथ कई सदस्यों की प्राथमिकताएं भी बदल गई है।
- बांदुंग में 1955 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कोशिश कर रही थी कि विकसित देश प्रतिद्वंद्वी कुओमिनतांग (चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी) की जगह उसे प्रतिनिधि मानें। ताइवान ने नैम के विचार का विरोध किया और साम्यवादी चीन, सोवियत संघ तथा बांदुंग के नए मंच से वैचारिक लड़ाई करने के लिए दक्षिण कोरिया और फिलीपींस की मदद से साम्यवादी विरोधी मंच (एपीएसीएल - एशियन पीपल्स एंटी कम्युनिस्ट लीग) बनाने की कोशिश की।
- बांदुंग में भी मतभेद थे और चीन को शामिल करने का विरोध हो रहा था। आज चीन आर्थिक विश्व शक्ति है, जिसने शीर्ष पर पहुंचने की दौड़ में कई देशों को पछाड़ दिया है। इस समय दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है, जहां कोरोनावायरस के शुरुआती प्रसार के लिए जिम्मेदार चीन धोखे, लालच और अक्खड़पन की वजह से प्रमुख विपक्षी और सभी का निशाना बन गया है।
- हालांकि गुट निरपेक्ष आंदोलन को परिभाषित करने वाले तरीकों, विषयों, उद्देश्यों और लक्ष्यों को लेकर मतभेद होता रहा है। कई लोग इसे तटस्थता भरा विचार कहेंगे तो कई इसे नैतिकतावादी मूल्यों से भरा संगठन कहेंगे, जहां मौजूद तथ्यों और उद्देश्यों के आधार पर ही फैसले लिए जाते हैं। दूर बैठकर देखना एक विकल्प हो सकता है मगर नैम ने लंबे समय से चल रहे कई अंतरराष्ट्रीय मसलों पर सक्रियता से काम किया है और उसके असर और नतीजे पर बेशक बहस होती रहे वह उन मुद्दों पर ध्यान देता रहा है। नैम और उसके मुखर नेताओं से महाशक्तियां कितनी भी नफरत करें दोनों पक्ष उसे खुश रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि विकासशील देशों

का बड़ा हिस्सा नैम में शामिल था। लेकिन ऐसा संयुक्त राष्ट्र समेत किसी भी बहुपक्षीय मंच के साथ होता है, जिसके संस्थागत ढांचे में ही उसके निष्प्रभावी होने के बीज छिपे हैं।

भारत की सक्रियता एवं गुटनिरपेक्षता

- जहां तक कूटनीतिक संवाद एवं संपर्क के उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करने का सवाल है, भारत की विदेश नीति अभी तक एकाग्र नहीं रही है। गहराते द्विपक्षीय संबंध ही अंतरराष्ट्रीय चर्चा में प्रमुख कारक रहे हैं। लेकिन भारत ने दुनिया को हमेशा पारस्परिक हितों तथा उद्देश्यों के चश्मे से देखा है और अकसर नए बहुपक्षीय मंच बनाने में वह अग्रणी रहा है। नैम ऐसा ही संगठन है मगर इकलौता संगठन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना में अहम भूमिका निभाई और इस संगठन में सदस्यों की संख्या अब बहुत अधिक है।
- इसी तरह जब ट्रंप जलवायु परिवर्तन और उसे रोकने के प्रयासों तथा प्रोटोकॉल पर आनाकानी कर रहे थे तो भारत ने मोर्चा संभाला। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत पूरी दुनिया को गंभीर वैश्विक प्रयास करने के लिए मना रहा है। आध्यात्मिक एवं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा मत एवं समर्थन प्राप्त हुआ तथा विभिन्न देशों ने उसे प्रायोजित भी किया। अब इसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह भारत के प्रभाव का बड़ा प्रदर्शन और उपलब्धि भी है और सांस्कृतिक कूटनीति का ताकतवर साधन भी।
- भारत ने अपने राष्ट्रहित को सुरक्षित रखने और उन्हें पूरा करने के लिए 1971 से असली राजनीति करना शुरू किया। इसे देखते हुए कुछ लोग आलेचना करते हैं कि भारत नैम में सर्वोच्च स्तर पर हिस्सेदारी करना नहीं चाहता है। आलोचना तब और भी मुखर हो गई, जब प्रधानमंत्री मोदी 2016 और 2019 की शिखर बैठकों में स्वयं हिस्सा नहीं ले सके। यह बात अलग है कि वहां भारत का प्रतिनिधित्व ऊंचे स्तर पर किया गया। जानकारों का मानना है कि क्षेत्रीय और वैश्विक आकांक्षाओं वाले भारत जैसे देश के लिए उच्च प्रतिनिधित्व वाले गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच से दूर रहना असंभव ही है।
- भारत "चुनिंदा एवं मुद्दा आधारित गठबंधन" और नैम समेत बहुपक्षीय मंचों के जरिये द्विपक्षीय संदर्भ में काफी सक्रिय है। भारत ने डिजिटल कूटनीति को शिखर बैठक के स्तर पर पहुंचा दिया है और उसने कोरोना वायरस के कारण आवाजाही एवं सीमाएं बंद होने के कारण इसे चलन में भी ला दिया है। यह सच है कि भारत ने मृतप्राय दक्षेस की उम्मीदों को नया जीवन दिया और जी-20 के मौजूदा मेजबान सऊदी को वर्चुअल शिखर बैठक की मेजबानी के लिए उत्साहित किया।
- द्विपक्षीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी तथा विदेश मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी भारतीय समुदाय के कल्याण एवं प्रमुख हितों तथा उद्देश्यों की सुरक्षा के लिए विश्व नेताओं से संपर्क करते आए हैं और बांग्लादेश से ब्राजील तक विभिन्न मित्र देशों को हर संभव सहायता प्रदान करते हैं। वास्तव में ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो भारत की जीवन रक्षक सहायता को "रामायण की संजीवनी बूटी" तक बताया।

आगे की राह

- मानवता कई दशकों के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। इस समय गुट निरपेक्ष देश वैश्विक एकजुटता को प्रोत्साहित करने में सहायक हो सकते हैं। गुट निरपेक्ष देश हमेशा विश्व का नैतिक स्वर रहे हैं और इस भूमिका को निभाने के लिए गुट निरपेक्ष देशों को समावेशी रहना होगा। कोविड-19 महामारी से उबरने के बाद दुनिया को वैश्वीकरण की एक नई व्यवस्था की आवश्यकता होगी। कोविड-19 ने हमें वर्तमान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की सीमाओं से परिचित कराया है। कोविड-19 से उबरने के बाद के विश्व में हमें पारदर्शिता, समानता और मानवता पर आधारित वैश्वीकरण की नई व्यवस्था की आवश्यकता होगी। हमें ऐसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की आवश्यकता है जो आज के विश्व का बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकें। भारत को केवल आर्थिक उन्नति ही नहीं बल्कि मानव कल्याण को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत ने लंबे समय तक इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सशक्त बनाने मे भारत की भूमिका महत्वूपर्ण रही है। भारत का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि गुटनिपरेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें।
- इसके अलावा आज की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष देशों को अपना अस्तित्व कायम रखने के लिये और अधिक सक्रिय सजग भूमिका निर्वाह करना होगा। गुटनिरपेक्ष देशों के नि:शस्त्रीकरण की भावना को प्रोत्साहित करते हुये अविकसित देशों में हस्तक्षेप की नीति को कम करने का प्रयास करने होगें। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण में गुट निरपेक्ष देशों को विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना होगा। शीत युद्ध एंव वारसा पैक्ट की समाप्ति के पश्चात गुटनिरपेक्षता का कोई ठोस राजनीतिक महत्व नहीं रह गया इसलिये इन राष्ट्रों को अपनी सार्थकता बनाये रखने के लिये आर्थिक क्षेत्र में प्रभावशील करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर 2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. आज की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियो में गुटनिरपेक्ष देशों को अपना अस्तित्व कायम रखने के लिये और अधिक सक्रिय और सजग भूमिका का निर्वाह करना होगा। चर्चा कीजिये।

06 चाबहार परियोजना का भविष्य और भारत

संदर्भ

- भारत सरकार ने चाबहार बंदरगाह परियोजना को वर्ष 2003 में हस्ताक्षरित किया। यह परियोजना पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण भारत-ईरान संबंधों का प्रतीक रही है। किन्तु हाल ही में खबर आई कि ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान ने यह कहते हुए भारत को इस डील से बाहर कर दिया है कि भारत इसके लिए राशि नहीं दे रहा है। हालांकि ईरान ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि भारत को चाबहार रेलवे प्रॉजेक्ट से बाहर करने का सवाल ही नहीं है।
- ईरान और भारत के बीच 2016 में चाबहार से अफगानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। ईरान के परियोजना से हाथ खींचने की अफवाह ऐसे समय आई है जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और हाल ही में चीन और ईरान के बीच 400 अरब डॉलर के रणनीतिक निवेश को लेकर समझौता हुआ है।

चाबहार परियोजना एवं उसका महत्व

- भारत कई वर्षों से अफगानिस्तान के साथ अपने व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ था किन्तु पाकिस्तान ने अरब सागर में भारत के व्यापार को अवरुद्ध किया हुआ था, इसलिए अरब सागर के किनारे बाईपास लेने की कोशिश भारत द्वारा की गयी।
- चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ओमान की खाड़ी में स्थित यह बंदरगाह ईरान के दक्षिणी समुद्र तट को भारत के पश्चिमी समुद्री तट से जोड़ता है। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी-पूर्वी समुद्री किनारे पर बना है। इस बंदरगाह को ईरान द्वारा व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के पश्चिम की तरफ मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर है। चाबहार परियोजना भारत के लिए रणनीतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण परियोजना रही है जिसके तहत भारत, ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय यातायात मार्ग स्थापित करना चाहता है।
- चाबहार भारत के लिए आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। चाबहार प्रोजेक्ट से भारत और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं और भारत एक बार ईरान तक पहुँच गया, तो वहाँ से उसके लिए रूस, यूरोप और मध्य एशिया तक का रास्ता खुल सकता है, सामानों के आयात-निर्यात की एक नई राह तैयार हो सकती है, साथ ही भारत दूसरे देशों से आयात पर होने वाले खर्च को कम कर सकता है। ईरान भारत के लिए गोल्डन गेट की तरह है। एक बार चाबहार परियोजना काम पूरा हो गया तो भारत द्वारा चाबहार से यूरोप तक सामान पहुँचाने में केवल दो दिन लगेंगे।
- चाबहार बंदरगाह युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के विकास के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत अफगानिस्तान के बामियन प्रांत के खनिज सम्पन्न हजिगाक क्षेत्र को चाबहार बन्दरगाह से जोड़ने के लिए 900 किलोमीटर की रेल लाइन बनाने पर भी विचार कर रहा है। एक अध्ययन के अनुसार इस प्रस्तावित रेल प्रोजेक्ट का बजट ईरान और अफगानिस्तान के लिए 5 बिलियन डॉलर तक हो सकता है जिसमें भारत इन दोनों देशों की बहुत बड़ी आर्थिक मदद कर सकता है। इस रेल नेटवर्क से भारत मध्य एशिया के अन्य देश कजाकिस्तान, उनबेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान तक अपनी पहुँच बना सकेगा।
- चाबहार समझौता भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसे इस क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन के प्रभाव को संतुलित करने का एक जरिया बताया जाता है।

चाबहार रेल लिंक प्रोजेक्ट

- चाबहार रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत भारत को बंदरगाह के कुछ हिस्सों (दो टर्मिनलों और पांच बर्थो) के विकास के लिए 10 साल की लीज मिली। साथ ही, उसे चाबहार से जाहेदान तक (628 किलोमीटर) रेलमार्ग बनाने के लिए भी बुलाया गया जो सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी है। भारत की ओर से इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (इरकॉन) को इस रेल ट्रैक के निर्माण में शामिल होना था। इरकॉन ने इस रेल प्रोजेक्ट के लिए सभी सेवाएं, सुपरस्ट्रक्टर वर्क और आर्थिक सहयोग (करीब +1.6 अरब) देने का वादा किया था।
- जानकारों के मुताबिक इरकॉन के इंजीनियर कई बार साइट पर गए और ईरानी रेलवे ने तैयारी भी कर ली थी, लेकिन भारत ने कभी काम शुरू नहीं किया। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे जाहिर तौर पर अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने का डर था। हालांकि अमरीका ने चाबहार बंदरगाह और जाहेदान तक रेल लाइन के काम को लेकर प्रतिबंधों में छूट दे दी थी, लेकिन जानकारों के मुताबिक, इक्विपमेंट सप्लायर और पार्टनर मिलने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से कोई भी इस काम में जुड़ना नहीं चाहता था।
- इसके अलावा ईरान की चीन से बढ़ती हुई दोस्ती भी भारत के इस प्रोजेक्ट के प्रति ढीला होने का एक कारण बना। हालाँकि भारत ने 2018 में चाबहार पोर्ट के एक टर्मिनल का संचालन अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद से भारत ने वहाँ से अफगानिस्तान को काफी कुछ सामान निर्यात भी किया है जिनमें अनाज और खाने की चीजें शामिल हैं।

चुनौतियाँ

- ईरान द्वारा चाबहार रेल लिंक प्रोजेक्ट परियोजना से हाथ खींचने की अफवाह ऐसे समय आई है जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है , इस बीच चीन और ईरान

के बीच तकरीन 400 अरब डॉलर डॉलर के रणनीतिक निवेश को लेकर समझौता हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान चीन को अगले 25 वर्षों तक बेहद सस्ती दरों पर कच्चा तेल देगा और बदले में चीन ईरान में बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। चूंकि ईरान ने चीन के साथ यह समझौता अमेरिका की पाबंदियों और धमकियों को दरकिनार कर किया है, इसलिए इसके दूरगामी प्रभाव होने के आसार जताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते का असर न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत समेत बाकी दुनिया पर भी पड़ेगा।

- जानकारों का कहना है कि चीन और ईरान के बीच यह समझौता भारत के लिए भी एक झटका हो सकता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत, ईरान से तेल आयात करना लगभग बंद कर चुका है जबकि कुछ साल पहले तक यह भारत के लिए तेल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता हुआ करता था। इसके अलावा, चीनी निवेश ईरान में जाने का नुकसान भी भारत को होगा।
- भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह को विकसित करना चाहता है और इसे चीन के पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट का जवाब माना जा रहा है। चाबहार भारत के लिए व्यापारिक और रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में चीन की मौजूदगी, भारतीय निवेश के लिए मुश्किलें पैदा करेंगी। इस डील की वजह से भारत के लिए स्थिति अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब बनाम ईरान जैसी हो सकती है।
- ईरान उम्मीद रखता है कि प्रतिबंधों के दौरान भारत उसकी कुछ ना कुछ मदद करेगा लेकिन अमेरिका का दबाव भारत पर इतना ज्यादा हो गया है कि अब उसे समझ आ गया है कि भारत के साथ दोस्ती बनाए रखना उसके लिए फायदेमंद नहीं है। जानकारों की राय में भारत-ईरान के रिश्ते अब ऐसे मोड़ पर पहुँचते जा रहे हैं जहाँ एक ने अमेरिका को दोस्त बना लिया, तो दूसरा दोस्त नाराज होकर चीन के पास चला गया है।

आगे की राह

- भारत और ईरान की दोस्ती की बुनियाद रही है दोनों की तटस्थता। शीतयुद्ध के दौर में, भारत ने हमेशा अमरीका की अगुवाई वाली पश्चिमी ताकतों और तत्कालीन सोवियत संघ की अगुवाई वाली कम्युनिस्ट शक्तियों से बराबर की दूरी बनाए रखी। किन्तु जानकारों का मानना है कि अब भारत, अमेरिका के कूटनीतिक फांस के और करीब होता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, ऐसे स्थिति में भी भारत द्वारा उसकी कोई मदद नहीं की जा रही है, जिससे वह नाराज होकर चीन के पास चला गया है। अगर भारत द्वारा सही समय पर ईरान की मदद नहीं की गयी तो जाहिर है आने वाले वक्त में चाबहार पोर्ट की लीज का एक्सटेंशन खतरे में पड़ सकता है।
- ईरान द्वारा चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई और सीपीईसी की जमकर तारीफ की गयी है। इसे ईरान की विदेश नीति में बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। ईरान का हालिया रुख मध्य-पूर्व क्षेत्र में शक्ति संतुलन के समीकरण बदलने का संकेत भी हो सकता है, इस क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व रहा है लेकिन अब चीन भी यहां अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। ईरान और चीन के बीच हुए आर्थिक और सुरक्षा समझौते से भारत की चिंता और बढ़ गई है। चीन और ईरान के बीच पार्टनरशिप डील के तहत, चीन चाबहार के ड्यूटी फ्री जोन और ऑयल रिफाइनरी फैसिलिटी में ईरान की मदद कर सकता है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि चीन चाबहार बंदरगाह में और बड़ी भूमिका में सामने आ सकता है।
- चाबहार और अमेरिका-ईरान के बीच संतुलन साधने में भारत के लिए अफगानिस्तान की भूमिका गेमचेंजर रही। फरवरी 2019 में अफगानिस्तान से पहली बार सामान चाबहार के जरिए ले जाया गया। इससे अफगानिस्तान में जरूरी स्थिरता के लिए इस बंदरगाह की अहमियत और साफ हुई। अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना धीरे-धीरे वापस बुला रहा है, ऐसे में वहां शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना अमेरिका और भारत के लिए जरूरी है। इसलिए भारत को सदियों पुराने दोस्त ईरान के साथ सामूहिक रणनीति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए।
- चीनी निवेश ने अफ्रीका के केन्या और एशिया के श्रीलंका जैसे देश को कर्जदार बनाकर छोड़ा है। ऐसे में भारत को चीन की विस्तारवादी नीति के बारे में ईरान को सचेत करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

Topic:

- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

प्र. चीनी निवेश ने अफ्रीका के केन्या और एशिया के श्रीलंका जैसे देश को कर्जदार बनाकर छोड़ा है। ऐसे में चीन-ईरान संबंधों को लेकर भारत की भूमिका को स्पष्ट करें।

07 वैश्विक जनसंख्या में वर्तमान प्रवृत्ति

चर्चा का कारण

- हाल ही में द लांसेट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आबादी साल 2064 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुँचेगी और फिर तेजी से घटेगी।

रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य

- इस रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की जनसंख्या वर्ष 2064 में अपने उच्चतम शिखर अर्थात लगभग 9.73 बिलियन होगी। इसके बाद वैश्विक स्तर पर जनसंख्या दर में तेजी से घटने का अनुमान लगाया गया है और कहा गया है कि सदी के अंत तक (अर्थात सन 2100 तक) विश्व की जनसंख्या घटकर 8.79 बिलियन रह जाएगी।
- संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में जनसंख्या से संबन्धित एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2100 तक दुनिया की आबादी अपने उच्चतम शिखर पर (लगभग 11 बिलियन) होगी; जबकि प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लांसेट की रिपोर्ट का कहना है कि वैश्विक आबादी का उच्चतम शिखर सन 2100 से पहले ही आएगा।
- लांसेट की रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी दुनिया की आबादी करीब 7.8 अरब है।
- द लांसेट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सदी के अंत तक में सबसे ज्यादा आबादी वाले पांच देश ये होंगे-भारत, नाइजीरिया, चीन, अमरीका और पाकिस्तान। रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया है कि नाइजीरिया दूसरे स्थान पर इसलिए होगा क्योंकि वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी होने के आसार कम हैं।

भारत से संबन्धित रिपोर्ट में बातें

- भारत के बारे में द लांसेट जर्नल की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में वर्ष 2047 के बाद से कमी आएगी।

- रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2047 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच जाएगी और उस समय देश की जनसंख्या लगभग 1.61 अरब होने का अनुमान लगाया गया है।
- द लांसेट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2010 से लेकर 2019 तक औसतन 1.2 फीसद रही है और इसी दर से भारत की जनसंख्या बढ़ती रही तो भारत चीन को वर्ष 2047 तक पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा।
- द लांसेट जर्नल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है की वर्ष 2047 के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से घटेगी और इस इस सदी के अंत तक (सन 2100 तक) भारत की आबादी घटकर सिर्फ एक अरब के करीब रह जाएगी अर्थात वर्तमान में जितनी है उससे 30-35 करोड़ कम हो जाएगी हालांकि फिर भी भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा।

विश्लेषण

- द लांसेट ने अपनी रिपोर्ट में वैश्विक जनसंख्या का शिखर पर पहुँचने का जो अनुमान व्यक्त किया है, वह संयुक्त राष्ट्र के अनुमान से लगभग 36 वर्ष पहले का है। इसके पीछे लांसेट का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में प्रजनन दर में कमी और बुजुर्गों की आबादी का ध्यान तो रखा गया है किन्तु अन्य मापदंडों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र के विपरीत द लांसेट की रिपोर्ट में वैश्विक प्रजनन दर के आँकड़े नवीन हैं, इसीलिए दोनों के निष्कर्षों में अंतर है।

भारत के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण

- भारत की जनसंख्या 2097 के बाद कम होने लगेगी, ऐसा यहाँ प्रजनन दर में कमी के कारण होगा।
- भारत में पहले की अपेक्षा अब लोगों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब भारत में महिला शिक्षा बढ़ रही है।
- शादी की उम्र में बढ़ोत्तरी और दो बच्चों के बीच अंतराल रखने में सरकारी प्रोत्साहन ने प्रजनन दर संतुलन रखने में प्रमुख भूमिका अदा की है।

- लांसेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आबादी घटेगी जरूर किन्तु फिर भी वह दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जायेगा, जो कि एक चिंता का विषय है। बढ़ती हुई आबादी और गरीबी का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाता है।
- कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में भारत में बेरोजगारी दर काफी अधिक है (कुछ रिपोर्ट के अनुसार पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक)। इस स्थिति में भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या कई तरह की समस्याएँ उत्पन्न कर सकती है।
- कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था पर काफी गंभीर प्रभाव डाले हैं। भारत में भारी संख्या में लोगों के रोजगार छिने हैं और औद्योगिक क्षेत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे सरकार के समक्ष और भी चुनौतियाँ खड़ी हो गयी हैं।
- कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि वर्ष 2040 के बाद भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्ग होने लगेगा, जिनकी देखभाल सुनिश्चित करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होगा।

सुझाव

- भारत सरकार को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) पर ध्यान देना चाहिए।

- भारत की जनसंख्या वर्तमान में युवा है, लेकिन यह हमेशा नहीं बनी रहेगी, अतः सरकार को ऐसी नीतियों को बनाना होगा जो श्रम गहन उद्योगों को भारत में विकसित कर सकें।
- भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है, अतः सरकार को कृषि क्षेत्र पर ध्यान देकर इसे लाभकारी बनाना चाहिए ताकि जनसंख्या का एक बड़ा भाग गुणवत्तापूर्ण जीवन बीता सके।

निष्कर्ष

- भारत सरकार को अपने मानव संसाधन को बेहतर बनाने हेतु स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर निवेश बढ़ाना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उचित क्रियान्वयन पर बल देना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-1

Topic:

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

प्र. हाल ही में प्रकाशित द लांसेट जर्नल की वैश्विक एवं भारत की जनसंख्या के निष्कर्षों की संक्षिप्त में चर्चा करते हुए बताएँ कि भारत को अपनी जनसंख्या नीति में किस प्रकार के सुधार करने चाहिए?

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 निष्ठा ऑनलाइन पोर्टल

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश के 1200 'की रिसोर्सेज पर्सन' (Key Resources Persons) के लिए पहला ऑन-लाइन NISHTHA कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- गौरतलब है कि यह अध्ययन परिणामों में सुधार लाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक प्रमुख कार्यक्रम -समग्र शिक्षा-के तहत प्रारंभिक चरण में शिक्षकों एवं विद्यालय प्रमुखों की समग्र उन्नति के लिए की गई एक राष्ट्रीय पहल है।

2. पृष्ठभूमि

- निष्ठा फेस-टू-फेस मोड में 21 अगस्त 2019 को ही लॉन्च किया गया था। इसके बाद, 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम समग्र शिक्षा के सहयोग से अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया।
- इनमें से 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा राज्य स्तर पर पूर्ण किया जा चुका है। 4 राज्यों (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर तथा बिहार) में राज्य स्तर पर प्रशिक्षण अभी प्रगति पर है।
- अभी तक लगभग 23,000 की रिसोर्सेज पर्सन तथा 17.5 लाख शिक्षकों एवं विद्यालय प्रमुखों को निष्ठा फेस टू फेस मोड में शामिल किया जा चुका है।

3. कोविड -19 और उसके पश्चात की स्थिति

- कोविड-19 महामारी के कारण अचानक हुए लॉकडाउन ने फेस टू फेस मोड में इस प्रोग्राम के संचालन को प्रभावित किया है। इसलिए, शेष 24 लाख शिक्षकों एवं विद्यालय प्रमुखों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निष्ठा को ऑनलाइन मोड के लिए कस्टमाइज किया गया है जिसका संचालन एनसीईआरटी द्वारा दीक्षा एवं निष्ठा पोर्टलों द्वारा किया जा रहा है।
- आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो निष्ठा पोर्टल के माध्यम से 1200 प्रमुख योग्य व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। ये रिसोर्स पर्सन आंध्र प्रदेश के शिक्षकों की प्रशिक्षण में सहायता करेंगे।

4. उद्देश्य

- निष्ठा के तहत विकसित मोड्यूल्स बच्चों के समग्र विकास पर फोकस करता है और इसलिए इसमें समावेशी शिक्षा स्वास्थ्य और कल्याण, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों, कला समेकित अध्ययन, स्कूली शिक्षा में पहल, विषय विशिष्ट अध्यापन शिक्षा, शिक्षण-अध्ययन में आईसीटी, नेतृत्व, पूर्व-विद्यालय शिक्षा, पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा आदि शामिल हैं।

5. महत्व

- यह न केवल छात्रों के शिक्षण परिणामों को बढ़ाने में मददगार होगा बल्कि उनके सर्वांगीण विकास में भी सहायता करेगा।
- यह भारतीय शिक्षकों को उनके वैश्विक दृष्टिकोण, समझ और शिक्षण के तरीकों को लगातार उन्नत करने में मदद करेगा।
- इसके अलावा यह शैक्षणिक मूल्यों को बढ़ावा देने और मानक शिक्षण विधियों का हिस्सा बनने में मदद करेगा।
- प्रौद्योगिकी अच्छे शिक्षकों का स्थान नहीं ले सकती जबकि प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित अच्छे शिक्षक शिक्षा के रूपांतरण में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। इस संदर्भ में आत्म-निर्भर भारत और एक भारत, श्रेष्ठ भारत को साकार बनाने के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित मूल्य आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक हैं।

02 श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर

1. चर्चा का कारण

- वर्ष 2011 के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में देवता की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए त्रावणकोर शाही परिवार के अधिकार को बरकरार रखा है।
- मंदिर 2011 के अपनी भूमिगत वाल्टों (गुबंद) में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के खजाने की खोज के बाद से चर्चा में है।

2. पृष्ठभूमि

- वर्ष 1947 के पूर्व, सभी मंदिर जो त्रावणकोर तथा कोचीन की पूर्ववर्ती रियासतों के नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन थे, स्वतंत्रता के पश्चात त्रावणकोर एवं कोचीन देवासम बोर्डों के नियंत्रण में आ गये।
- 1949 में त्रावणकोर और कोचीन के शाही परिवार और भारत सरकार के बीच अनुबंध के अनुसार श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का प्रशासन 'त्रावणकोर के शासक' के पास रहेगा।
- इसके उपरान्त त्रावणकोर कोचीन हिंदू रिलीजियस इंस्टिट्यूशंस एक्ट के सेक्शन 18(2) के तहत मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर के शासक के नेतृत्व वाले ट्रस्ट के हाथ में रहा।
- वर्ष 1971 में, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पूर्ववर्ती राजघरानों के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया तथा उनके विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया।

3. मुख्य मुद्दा

- त्रावणकोर के आखिरी शासक के निधन उपरान्त केरल सरकार ने उनके भाई उत्राटम तिरुनाल मार्तण्ड वर्मा के नेतृत्व में प्रशासकीय समिति के पास मंदिर का प्रबंधन सौंपा।
- मंदिर के तहखानों में जमा संपत्ति पर राज परिवार का अधिकार होने का दावा कर मार्तण्ड वर्मा 2007 में कोर्ट में मामला ले गए थे जिसके उपरान्त भक्तों ने याचिका लगाई कि त्रावणकोर शाही परिवार को मंदिर की संपत्ति का बेवजह इस्तेमाल की अनुमति न दी जाए।
- केरल की एक निचली अदालत ने राज परिवार के दावे के खिलाफ एक निषेधाज्ञा पारित की जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट चला गया।
- हाईकोर्ट ने 2011 के फैसले में आदेश पारित किया कि मंदिर के मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाए जिसके विरुद्ध राज परिवार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फौरन याचिका दायर की।
- क्योंकि इसके तहत मुख्य कानूनी प्रश्न यह था, कि क्या अंतिम शासक की मृत्यु के बाद उनके भाई, उत्रेदम थिरुनल मार्तण्ड वर्मा 'त्रावणकोर का शासक' होने का दावा कर सकते हैं।

4. सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

- अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चार हफ्ते में प्रबंधन और सलाहकार समिति का गठन किया जाए और इन समितियों का पीठाधीश हिन्दू होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मंदिर की तमाम संपत्तियों को संरक्षित करने की इन समितियों की जिम्मेदारी होगी।
- पद्मनाभस्वामी मंदिर के तहखाने (कल्लरा बी) को खोला जाए या नहीं इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने प्रबंधन और सलाहकार समिति पर छोड़ दिया है।
- न्यायालय ने, नीतिगत मामलों पर प्रशासनिक समिति को सलाह देने के लिए एक दूसरी समिति गठित करने का भी आदेश दिया।
- इसकी अध्यक्षता केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।
- इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का कहना है कि, प्रथागत कानून के अनुसार, देवता के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार (Shebait Rights) अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी परिवार के सदस्यों के साथ जारी रहता है।
- उच्चतम न्यायालय ने 'शीबैट' (Shebait) को 'प्रतिमा के संरक्षक, सांसारिक प्रवक्ता तथा अधिकृत प्रतिनिधि' के रूप में परिभाषित किया है, जो इसके सांसारिक मामलों तथा इसकी परिसंपत्तियों का प्रबंधन करेगा।

5. श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर

- श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर केरल के तिरुअनन्तपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध वैष्णव हिन्दू मंदिर है।
- इसका जिक्र 9 वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है, लेकिन मंदिर के मौजूदा स्वरूप को 1733 ई. में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने बनवाया था।
- इस मंदिर का वास्तुशिल्प द्रविड़ एवं केरल शैली का मिला-जुला रूप है।
- इस मंदिर का गोपुरम द्रविड़ शैली में बना हुआ है जिसमें सुंदर नक्काशी की गयी है।
- मंदिर के पास ही एक सरोवर भी है, जो 'पद्मतीर्थ कुलम' के नाम से जाना जाता है।

03 अल–अमल (Hope Mission)

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केन्द्र से अपना अंतरिक्षयान सफलता पूर्वक प्रक्षेपित कर नया इतिहास रचा है।
- होप प्रोब नामक इस मिशन को एच-टू-ए नाम के प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया।

2. पृष्ठभूमि

- वर्ष 2021 UAE के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2021 में UAE अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरा करेगा यह इस संदर्भ में और महत्वपूर्ण हो जाता है कि होप प्रोब भी फरवरी 2021 तक मंगल पर पहुँच सकता है।
- इस मिशन को संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। इसका अरबी नाम Al-Amal तथा अंग्रेजी नाम Hope रखा गया है।

3. होप प्रोब

- यह मंगल की कक्षा में पहुंचने के बाद एक मंगलवर्ष यानी 687 दिनों तक उसकी कक्षा में चक्कर लगायेगा।
- इसमें लगा हाई रिजोल्यूशन कैमरा कई एंगल से किसी क्षेत्र की तस्वीर खींचकर भेजने में सफल होगा। इसमें लगा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर मंगल के पर्यावरण संबंधी डाटा/डेटा को संकलित करेगा।
- इसमें इंन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया है जो मंगल के वातावरण के तापमान तथा जल एवं बर्फ के संभावित उपस्थिति का पता लगायेगा।
- इस स्पेसक्रॉफ्ट में 900 वॉट के सोलर पैनल लगाये गये हैं जो ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
- इसमें लगा 1.5 मीटर का एंटिना पृथ्वी से कम्यूनिकेशन स्थापित करने में सहायक होगा।

4. उद्देश्य

- अभी इस मिशन का उद्देश्य मंगल के पर्यावरण और मौसम का अध्ययन करना है लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा लक्ष्य अगले 100 सालों में मंगल पर इंसानी बस्ती बनाने का भी है।
- इस स्पेसक्रॉफ्ट के माध्यम से मंगल के वायुमंडल में मिथेन, ऑक्सीजन आदि गैसों की उपस्थिति का अध्ययन किया जायेगा।
- उम्मीद की जा रही है कि सितंबर 2021 तक मंगल से डेटा पृथ्वी तक आने लगेगा, जिसे विश्व समुदाय के लिए खुला रखा जायेगा।
- सूखे नदी तल और खनिजों से मिलते-जुलते साक्ष्य इंगित करते हैं कि प्राचीनतम मंगल वातावरण बहुत गर्म था।
- इसलिए, वैज्ञानिक मंगल पर मौजूद पिछले वातावरण का अध्ययन करना चाहते हैं, ताकि यह समझा जा सके कि समय के साथ किसी ग्रह की वासशीलता कैसे बदल सकती है।

5. मंगल का क्षयकारी वातावरण

- वर्ष 2017 में, नासा के MAVEN अंतरिक्ष यान ने खुलासा किया कि सौर हवा और विकिरण ने मंगल के वातावरण को नष्ट कर दिया था, जो अरबों साल पहले जीवन की उत्पत्ति कर सकता था।
- इस विनाश ने मंगल के वातावरण को बहुत ठंडा और दुर्बल बना दिया, मंगल की सतह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी का लगभग 0.6 प्रतिशत (101,000 पास्कल) है।
- मंगल के वातावरण में सूर्य के विकिरण या धूल भरी आंधियों से कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए किसी भी मानव ने अभी तक मंगल पर पैर नहीं रखा है।
- इसके अलवा इसके दुर्बल वातावरण में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड (लगभग 96 प्रतिशत) है, साथ ही आर्गन और नाइट्रोजन जैसी अन्य गैसें मामूली मात्रा में हैं।
- यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यहां जीवित रहना मुश्किल है।

04 ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले

1. चर्चा का कारण

- कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच शहरों की बड़ी आबादी गांव की तरफ वापस गई है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर प्रवासियों की घर वापसी हुई थी, जिसके बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में 30 से 80 फीसदी तक मरीजों के आंकड़ों में बीच उछाल दर्ज की गई है।

2. प्रमुख बिन्दु

- कई जगहों पर अपने क्षेत्रों तक पहुंचे श्रमिकों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भी हुई। ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो सकती है।
- बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल (आंध्र प्रदेश और केरल के अलावा) जैसे राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने नीति निर्माताओं के लिए अधिक चुनौतियां पेश की हैं।
- कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का भी दावा है कि अगस्त तक भारत में संक्रमितों की संख्या 15 लाख से ज्यादा हो सकती है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत में मौजूदा मेडिकल इंफ्रॉस्ट्रक्चर और मेडिकल उपकरणों की संख्या काफी कम है।

3. भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की लगभग 69 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को और बेहतर भारत सरकार की ही रिपोर्ट नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 से समझा जा सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 21,403 सरकारी अस्पताल (प्राथमिक, सामुदायिक और उप-जिला / मंडल अस्पताल को मिलाकर) हैं जिनमें 2,65,275 बेड हैं, जबकि शहरों के 4,375 अस्पतालों में 4,48,711 बेड हैं।
- देश में तो वैसे हर 1,700 मरीजों पर एक बेड है लेकिन ग्रामीण भारत में इसकी स्थिति चिंताजनक है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3,100 मरीजों पर एक बेड है। राज्यों की बात करें तो इस मामले में बिहार की स्थिति सबसे खराब है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 10 करोड़ आबादी रहती है जिनके लिए कुल 1,032 अस्पताल हैं जिनमें महज 5,510 बेड हैं। इस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 18,000 ग्रामीणों के लिए एक बेड की व्यवस्था है।
- वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 77 फीसदी (15 करोड़ से ज्यादा) आबादी गांवों में रहती है, जिनके लिए 4,442 अस्पताल और कुल 39,104 बेड हैं। लगभग 3,900 मरीज पर एक बेड की व्यवस्था है। तमिलनाडु इस मामले में सबसे अच्छी स्थिति में है जहां के ग्रामीण क्षेत्र में कुल 40,179 बेड हैं और कुल 690 सरकारी अस्पताल हैं। इस हिसाब से तमिलनाडु में हर बेड पर लगभग 800 मरीज हैं।
- रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की मानें तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 की आबादी पर महज एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) कहता है कि हर 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होने चाहिए, वहीं पूरे देश की बात करें तो देश में 10,000 की आबादी पर लगभग सात डॉक्टर हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के यहां रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टरों की कुल संख्या लगभग 1.1 करोड़ है।

05 सक्रिय औषधीय सामग्री पर टीआईएफएसी की रिपोर्ट

1. चर्चा का कारण

- भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टीआईएफएसी) द्वारा हाल ही में सक्रिय औषधीय सामग्री- स्थिति, मुद्दे, प्रौद्योगिकी तत्परता और चुनौतियां' शीर्षक पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

2. प्रमुख बिन्दु

- रिपोर्ट में कहा गया है कि सक्रिय औषधीय सामग्री (एपीआई) के स्वदेशी उत्पादन को उस स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए, जहां उत्पादन आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो।
- रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि भारतीय एपीआई उद्योग के लिए एक संभावित क्षेत्र जैसे एंजाइमैटिक अभिक्रियाओं या फरमेंटेशन से जुड़े मध्यवर्ती उत्पादन के लिए बॉयोकेटालाईसिस के माध्यम से काइरल और एंटीवायरल दवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिनके लिए न्यूक्लिक एसिड ब्लॉक्स- थायमिडाइन/साइटोसिन एडेनिन/गुआनिन की आवश्यकता होती है।
- रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि रासायनिक घटकों जैसे स्टेरॉयड, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोसाइड्स आदि में काम करने वाली भारतीय कंपनियों को सरकारी प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि प्रौद्योगिकी विकास और व्यावसायीकरण के लिए अकादमिक-उद्योग से करीबी संपर्क की आवश्यकता के साथ-साथ प्रौद्योगिकी विकास अथवा त्वरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहयोग दिया जा सके।
- रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि भारतीय एपीआई उद्योग के लिए एक संभावित क्षेत्र जैसे एंजाइमैटिक अभिक्रियाओं या फरमेंटेशन से जुड़े मध्यवर्ती उत्पादन के लिए बॉयोकेटालाईसिसके माध्यम से काइरल और एंटीवायरल दवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिनके लिए न्यूक्लिक एसिड ब्लॉक्स- थायमिडाइन/साइटोसिन एडेनिन/गुआनिन की आवश्यकता होती है। इनमें से किसी का भी सायनीकरणपौधों की कमी के कारण भारत में निर्माण नहीं होता हैं।
- चीन से आयात लगातार बढ़ रहा है और अब यह लगभग 68 प्रतिशत हो गया है। इसका निराकरण करने के लिए ही, टीआईएफएसी ने हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लघु और मध्यम अवधि में एपीआई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नई नीतियों की सलाह दी है।

3. सक्रिय औषधीय सामग्री क्या है

- सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) को आमतौर पर 'ड्रग पदार्थ' या 'बल्क फार्मास्युटिकल केमिकल' के रूप में जाना जाता है। एपीआई (API) वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो किसी दवा के उत्पादन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल होते हैं।

4. भारतीय दवा उद्योग

- भारतीय दवा उद्योग जीवन रक्षक तथा आवश्यक दवाओं का उत्पादन करने के लिए चीन से आयातित होने वाले ऐक्टिव फॉर्मास्युटिकल्स इनग्रेडिएंट या एपीआई तथा इंडरमीडियेट्स पर अत्यधिक निर्भर है।
- चीन और इटली के बाद फार्मास्युटिकल उद्योग के मामले में,भारत का व्यापार दुनिया में तीसरे स्थान पर है और मूल्य की दृष्टि से दुनिया में चौदहवें स्थान पर है। भारत के पास3,000 औषध उद्योगों का मजबूत नेटवर्क है और लगभग 10,500 विनिर्माण इकाइयां हैं । 2019 में देश में 1.4 लाख करोड़ रुपये (20.03 बिलियन अमरीकी डॉलर) के घरेलू कारोबार के साथ दुनिया के 200 से अधिक देशों को निर्यात किया गया हैं।

06 गैर–व्यक्तिगत डेटा

1. चर्चा का कारण

- सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपाल कृष्णन की अध्यक्षता में गठित समिति ने सुझाव दिया है कि भारत को ऑनलाइन एकत्र की गई जानकारी के शेयरिंग, मुद्रीकरण (monetization) और सूचनाओं की प्राइवेसी की निगरानी के लिए एक नए डेटा रेगुलेटर की जरूरत है।
- समिति ने रिपोर्ट में सरकार को गैर-व्यक्तिगत डेटा की रूपरेखा के प्रस्तावित नियमों पर सुझाव दिये हैं।

2. प्रमुख बिन्दु

- समिति ने सुझाव दिया है कि देश में उत्पन्न गैर-व्यक्तिगत डेटा को विभिन्न घरेलू कंपनियों और संस्थाओं द्वारा दोहन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- इसने एक नए प्राधिकरण की स्थापना का भी सुझाव दिया है जो इस तरह के गैर-व्यक्तिगत डेटा के उपयोग और उसकी निगरानी के लिए सशक्त होगा।

3. गैर-व्यक्तिगत डेटा क्या है

- गैर-व्यक्तिगत डेटा उन जानकारी से संबंधित है जिसमें नाम, आयु या पता जैसे कोई विवरण शामिल नहीं हैं, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।
- उदाहरण के लिये किसी खाद्य वितरण सेवा प्रदान करने वाली कंपनी द्वारा मुख्य रूप से व्यक्ति का नाम, आयु, लिंग और अन्य संपर्क (Contact) संबंधी जानकारी मांगी जाती है। अब यदि डेटा के इस समूह से नाम और संपर्क संबंधी सूचना हटा दी जाए तो यह गैर-व्यक्तिगत डेटा बन जाएगा और इसके आधार पर किसी व्यक्ति विशिष्ट की पहचान करना संभव नहीं होगा।
- सरकारी समिति (जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है) ने डेटा के स्रोत और इस तथ्य के आधार पर कि डेटा के माध्यम से व्यक्ति विशिष्ट की पहचान की जा सकती है अथवा नहीं गैर-व्यक्तिगत डेटा को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया है-सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा, सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा और निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा।

4. सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा

- सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा में शामिल हैं - सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा एकत्र किये गए सभी प्रकार के डेटा जैसे- जनगणना, नगर निगम द्वारा कर रसीद के माध्यम एकत्र डेटा और सभी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित कार्यों के निष्पादन के दौरान एकत्र की गई जानकारी इत्यादि।

5. सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा

- सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा के अंतर्गत व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह से संबंधित डेटा को शामिल किया गया है, जैसे- एक ही भौगोलिक स्थिति साझा करने वाले लोगों का डेटा, धर्म, नौकरी, या अन्य सामान्य सामाजिक हित समुदाय, एक जैसा रोजगार करने वाले लोगों का डेटा आदि। उदाहरण के लिए सार्वजनिक परिवहन संबंधी सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों, टेलीकॉम कंपनियों, बिजली वितरण कंपनियों आदि द्वारा एकत्र डेटा।

6. निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा

- निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा की श्रेणी में उस डेटा को शामिल किया गया है, जो कि एक व्यक्ति विशिष्ट या सॉफ्टवेर के माध्यम से एकत्र किया जाता है।

7. गैर-व्यक्तिगत डेटा कितना संवेदनशील हो सकता है?

- व्यक्तिगत डेटा के विपरीत, जिसमें किसी व्यक्ति के नाम, आयु, लिंग, यौन अभिविन्यास, बायोमेट्रिक्स और अन्य आनुवंशिक विवरणों के बारे में स्पष्ट जानकारी होती है, गैर-व्यक्तिगत डेटा से किसी व्यक्ति विशिष्ट की पहचान करना बेहद मुश्किल है। हालांकि, कुछ श्रेणियों में जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित डेटा या सरकारी प्रयोगशालाओं या अनुसंधान संस्थाओं के रणनीतिक महत्व वाले डेटा अगर गलत हाथों में चले गए तो यह भारत के लिये सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो सकता है।
- इसके अलावा अगर किसी समुदाय के स्वास्थ्य से संबंधित गैर-व्यक्तिगत डेटा का मुक्त प्रवाह भी खतरनाक साबित हो सकता है। समिति ने कहा कि यदि मूल व्यक्तिगत डेटा संवेदनशील प्रकृति का हो तो ऐसे नुकसान की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं।

07 दल बदल विरोधी अधिनियम एवं न्यायिक समीक्षा

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा कांग्रेसी नेता सचिन पायलट और 18 अन्य असंतुष्ट विधायकों को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता नोटिस जारी किया था। इस अयोग्यता नोटिस को विधायकों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, किन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पीकर के नोटिस पर फिलहाल रोक लगाते हुए यथा स्थिति को बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं।
- इन असंतुष्ट विधायकों का तर्क है कि विधानसभा के बाहर कुछ नेताओं के निर्णयों और नीतियों से असहमत होने के आधार पर उन्हें संसदीय 'दलबदल विरोधी कानून' के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है।

2. मामला क्या था?

- राजस्थान सरकार में उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के कुछ बागी विधायक हाल ही में कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में बार-बार निमंत्रण देने के बावजूद शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद राज्य में पार्टी के मुख्य सचेतक की अपील पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इन विधायकों को अयोग्यता संबंधी नोटिस जारी किया गया था।

3. असंतुष्ट विधायकों का पक्ष

- बागी (REBEL) विधायकों ने अपनी रिट याचिका में नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया है कि उनके द्वारा सदन की सदस्यता का त्याग नहीं किया गया है, इसलिए 'दल बदल विरोधी कानून' का उन पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, और न ही बैठकों में शामिल न होने में विफल रहने के आधार पर उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- बागी विधायकों के द्वारा रिट याचिका राजस्थान विधानसभा सदस्यों की वैधता (पार्टी बदलने के आधार पर अयोग्यता) नियम', 1989 और संविधान की दसवीं अनुसूची के क्लॉज 2(1)(।) को चुनौती देने के लिये दायर की गई है, जो कहता है कि स्वेच्छा से एक राजनीतिक पार्टी की सदस्यता का त्याग करने पर सदस्य दल बदल कानून के तहत अयोग्यता के लिये उत्तरदायी होगा।

4. विधानसभा अध्यक्ष का पक्ष

- जब तक विधानमंडल के सभापति द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत सदस्यों को अयोग्यता पर अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक न्यायपालिका अयोग्यता कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है।

5. किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू

- इस वाद में न्यायालय ने कहा कि सभापति द्वारा दल बदल विरोधी कानून के तहत अंतिम निर्णय लेने से पहले की गई कार्यवाही की बीच में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है । हालांकि इसी वाद में न्यायपालिका ने निर्णय दिया था कि दल बदल विरोधी कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिये गए निर्णय में त्रुटियों की जाँच का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।
- अंतर्वर्ती अयोग्यता' (INTERLOCUTORY DISQUALIFICATIONS) या निलंबन ऐसे मामले हैं जिनके गंभीर, तत्काल और अपरिवर्तनीय नतीजे और परिणाम हो सकते हैं, इसलिए इन पर न्यायालय बीच में दखल दे सकता है ।
- न्यायपालिका केवल संवैधानिक जनादेश के उल्लंघन पर आधारित दुर्भावना, प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन नहीं करने और दुराग्रह के मामलों में ही न्यायिक समीक्षा करेगा।

6. दल बदल विरोधी कानून

- दसवीं अनुसूची को 1985 में 52 वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में डाला गया था। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के रूप में प्रश्न पर निर्णय ऐसे सदन के अध्यक्ष या अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। ये कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है।
- यदि किसी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, या अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत, वोट नहीं देता है या विधायिका में वोट नहीं करता है। यदि सदस्य ने पूर्व अनुमति ले ली है, या इस तरह के मतदान या परहेज से 15 दिनों के भीतर पार्टी द्वारा निंदा की जाती है, तो सदस्य को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 निष्ठा ऑनलाइन पोर्टल

प्र. निष्ठा ऑनलाइन पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. निष्ठा ऑनलाइन पोर्टल को 21 अगस्त 2108 को लॉन्च किया गया था।
2. आंध्रप्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जो निष्ठा पोर्टल के माध्यम से 1200 प्रमुख ज्ञानी व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (b)

व्याख्याः निष्ठा ऑनलाइन पोर्टल फेस-टू-फेस मोड में 21 अगस्त 2018 को लॉन्च नहीं किया गया था अपितु 21 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। इसीलिए कथन (a) असत्य है एवं कथन (b) सत्य है। इसीलिए उत्तर (b) होगा।

02 श्री पद्मनामस्वामी मंदिर

प्र. दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए-

(a) श्री पद्मनामस्वामी मंदिर का गोपुरम द्रविड़ शैली में बना हुआ है।

(b) मंदिर के पास ही एक सरोवर भी है, जो 'पद्मनामस्वामी सरोवर' के नाम से जाना जाता है।

(c) श्री पद्मनामस्वामी मंदिर आंध्रप्रदेश के अमरावती में स्थित भगवान विष्णु का मंदिर है।

(d) इस मंदिर का वास्तुशिल्प गंधारशैली में बना हुआ है।

उत्तरः (a)

व्याख्याः श्री पद्मनामस्वामी मंदिर के पास ही एक सरोवर भी है, जो 'पद्मतीर्थ कुलम' (न कि 'पद्मनामस्वामी सरोवर') के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर केरल के तिरुअनंतपुरम (न की आंध्रप्रदेश) में स्थित है। इस मंदिर का वास्तुशिल्प द्रविड़ शैली (न कि गंधार शैली) में बना हुआ है। इस तरह कथन (b), (c) और (d) गलत हैं, अतः उत्तर (a) होगा।

03 अल-अमल

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्षयान प्रक्षेपित किया।
2. इस मिशन को संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर द्वारा निष्पादित किया गया।
3. इस अंतरिक्षयान के माध्यम से चन्द्रमा के वातावरण में मिथेन, ऑक्सीजन आदि गैसों की उपस्थिति का अध्ययन किया जायेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (b)

व्याख्याः हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केन्द्र से अपना अंतरिक्षयान प्रक्षेपित कर नया इतिहास रचा है। इस स्पेसक्रॉफ्ट के माध्यम से मंगल (न कि चन्द्रमा) के वातावरण में मिथेन, ऑक्सीजन आदि गैसों की उपस्थिति का अध्ययन किया जायेगा। इस तरह कथन 3 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

04 ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले

प्र. निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए-

(a) अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में कोरोना का चरम असर अगस्त माह में देखा जाएगा।

(b) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की लगभग 52% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

(c) एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 21,403 सरकारी अस्पताल हैं।

(d) रूरल हेल्प स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 की आबादी पर महज एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं।

उत्तर: (b)

व्याख्या: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की लगभग 69 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में इसका प्रभाव चरम स्तर पर अगस्त माह में देखा जाएगा। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 की आबादी पर महज एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, जबकि WHO के अनुसार प्रत्येक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होने चाहिए। इस तरह कथन (b) असत्य है, इसलिए उत्तर (b) होगा।

05 सक्रिय औषद्यीय सामग्री पर टीआईएफएसी की रिपोर्ट

प्र. सक्रिय औषद्यीय सामग्री पर टीआईएफएसी की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) को आमतौर पर 'ड्रग पदार्थ' या 'बल्क फार्मास्युटिकल केमिकल' के रूप में जाना जाता है।
2. एपीआई वे रासायनिक यौगिक होते हैं, जो किसी दवा के उत्पादन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल होते हैं।
3. फार्मास्युटिकल उद्योग के मामले में भारत का व्यापार दुनिया में 5वें स्थान पर है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 व 3 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 2 (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (c)

व्याख्या: चीन और इटली के बाद फार्मास्युटिकल उद्योग के मामले में भारत का व्यापार दुनिया में तीसरें स्थान (न कि 5वें) पर है और मूल्य के दृष्टि से दुनिया में चौदहवें स्थान पर है। एपीआई वे रासायनिक यौगिक होते हैं, जो किसी दवा के उत्पादन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल होते हैं। इस तरह कथन 3 असत्य है, अतः उत्तर (c) होगा।

06 गैर-व्यक्तिगत डेटा

प्र. गैर-व्यक्तिगत डेटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. गैर-व्यक्तिगत डेटा उन जानकारी से संबंधित है, जिसमें नाम, आयु या पता जैसे कोई विवरण शामिल नहीं हैं।
2. निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा की श्रेणी में उस डेटा को शामिल किया जाता है, जो कि एक व्यक्ति विशिष्ट या साफ्टवेयर के माध्यम से एकत्र किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपाल कृष्णन की अध्यक्षता में गठित समिति ने भारत को ऑनलाइन एकत्र की गई जानकारी के शेयरिंग, मुद्रीकरण और निगरानी के लिए एक डेटा रेगुलेटर की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस संदर्भ में दिए गये दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए उत्तर (c) होगा।

07 दल-बदल विरोधी अधिनियम

प्र. दल-बदल विरोधी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. दसवीं अनुसूची को वर्ष 1980 में 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था।
2. किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू वाद में न्यायालय ने कहा कि सभापति द्वारा दल-बदल विरोधी कानून के तहत लिए गये अंतिम निर्णय पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: दसवीं अनुसूची को वर्ष 1985 में 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। उल्लेखनीय है कि किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू वाद में न्यायालय ने कहा कि सभापति द्वारा 'दल-बदल विरोधी कानून' के तहत अंतिम निर्णय लेने से पहले की गई कार्यवाही की बीच में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। इस तरह कथन 1 असत्य है, अतः उत्तर (b) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 विश्व बाघ दिवस

- अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में संेट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट से हुई थी। इसका उद्देश्य बाघ के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना व बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है।
- साल 2018 की रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर 2,967 हो गई है। पहले हुई गणना के लिहाज से देखा जाए तो साल 2014 के मुकाबले 741 बाघों की बढ़ोतरी हुई है। पूरे देश में सबसे अधिक बाघों के साथ उत्तराखंड का जिम कार्बेट नैशनल पार्क पहले स्थान पर है। यहाँ 231 बाघ हैं। यहां बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2006 में जिम कार्बेट में बाघों की संख्या 137 थी जो बढ़कर 2010 में 174 और 2014 में 215 हो गई।
- कार्बेट के बाद बाघों की संख्या कर्नाटक के नागरहोल (127) और बांदीपुर (126) में अधिक है। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ और असम का काजीरंगा नैशनल पार्क है जहां बाघों की संख्या बराबर 104-104 है। पांचवे नंबर पर 103 बाघों के साथ तमिलनाडु का मुदुमलई है। यदि राज्यों के स्तर पर देखें तो मध्य प्रदेश इस लिस्ट में सबसे ऊपर है जहां लगभग 526 बाघ हैं जबकि दूसरे नंबर पर कर्नाटक है जहां बाघों की संख्या 524 है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है जहां 442 बाघ हैं।

- हर चार साल में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के तहत बाघों की गिनती की जाती है। आखिरी बार यह गणना 2018 में हुई थी।
- बाघ संरक्षण के काम को प्रोत्साहित करने, उनकी घटती संख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए साल 2010 में रूस के संेट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। इस सम्मेलन में मौजूद विभिन्न देशों की सरकारों ने 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया था।
- उल्लेखनीय है कि बाघों के संरक्षण को लेकर भारत अब दुनिया के दूसरे देशों की मदद करेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने दुनियाभर में 13 ऐसे देशों की पहचान की है, जहां मौजूदा समय में बाघ पाए जाते हैं, लेकिन संरक्षण के अभाव में इनकी संख्या कम है। ऐसे में भारत इन देशों को बाघों के संरक्षण के लिए बेहतर तकनीक और योजना मुहैया कराएगा।

02 डिजिटल शिक्षा पर "भारत रिपोर्ट-2020"

- हाल ही में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" द्वारा डिजिटल माध्यम से डिजिटल शिक्षा पर "भारत रिपोर्ट-2020" जारी किया गया। इस रिपोर्ट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने और उनके सीखने के क्रम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनाए गए अभिनव तरीकों की विस्तृत व्याख्या की गयी। रिपोर्ट को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों के परामर्श से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के डिजिटल शिक्षा प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने शिक्षा को एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया है जिसका लक्ष्य प्री-नर्सरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक स्कूलों के व्यापक स्पेक्ट्रम में डिजिटल शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है।
- उल्लेखनीय है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों को सीखने की उनकी ललक में मदद करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि "दीक्षा मंच", "स्वयं प्रभा टीवी चैनल",

ऑनलाइन एमओओसी पाठ्यक्रम, "शिक्षा वाणी", दिव्यांगों के लिए एनआईओएस द्वारा विकसित "डेजी, ई-पाठशाला", "ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (एनआरओईआर) की राष्ट्रीय रिपोजिटरी", टीवी चौनल, ई-लर्निंग पोर्टल, वेबिनार, और पुस्तकों के वितरण सहित राज्य/केन्द्र शासित सरकारों के साथ अन्य डिजिटल पहल।

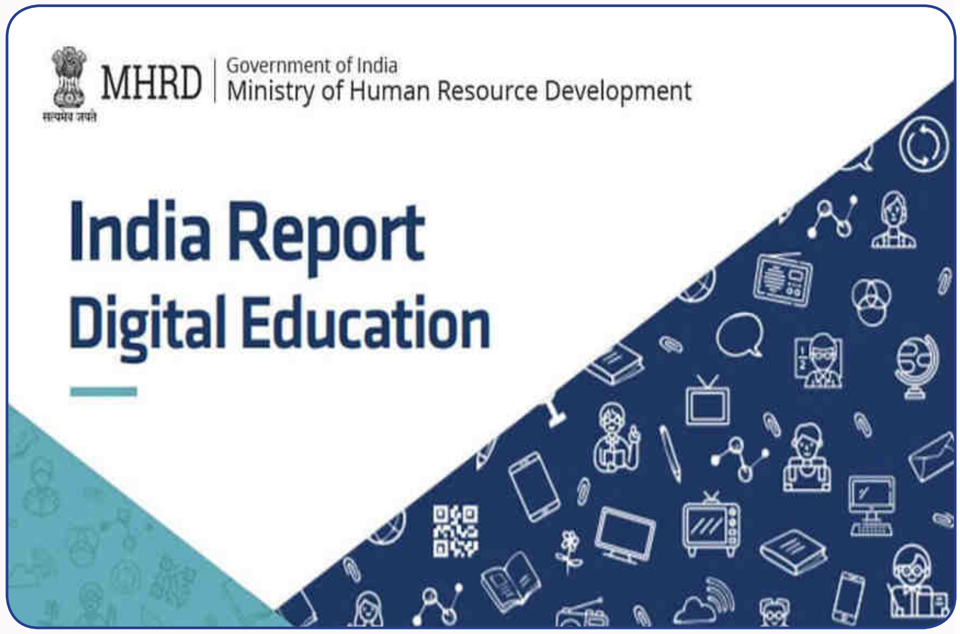

राज्यों की प्रमुख डिजिटल पहलें

- राज्य सरकारों द्वारा की गई कुछ प्रमुख डिजिटल पहलों में राजस्थान में "स्माइल" (सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट), जम्मू में "प्रोजेक्ट होम क्लासेस", छत्तीसगढ़ में "पढ़ाई तुहार दुवार" (आपके द्वार पर शिक्षा), दिल्ली में एनसीटी का अभियान "बुनियाद", केरल का अपना शैक्षिक टीवी चैनल (हाई-टेक स्कूल प्रोग्राम), "ई-विद्वान पोर्टल" और साथ ही मेघालय में शिक्षकों के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम शामिल हैं।"उन्नयन बिहार पहल" के तहत बिहार सरकार ने छात्रों के लिए "मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय" शुरू किया है। असम ने कक्षा 6 से 10 के लिए "बिस्वा विद्या असम मोबाइल एप्लिकेशन" लॉन्च किया है। उत्तराखंड "संपर्क बैंक ऐप" का उपयोग कर रहा है, जिसके माध्यम से प्राथमिक स्कूल के छात्र एनिमेटेड वीडियो, ऑडिओ, वर्कशीट, पहेलियों आदि का उपयोग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश ने टॉप पैरेंट ऐप लॉन्च किया है, जो एक नि:शुल्क मोबाइल ऐप है जो छोटे बच्चों (3-8 साल) के माता-पिता को बाल विकास के ज्ञान और व्यवहारों की सीख देता है। यहीं नहीं तेलंगाना में कोविड संकट के दौरान शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है।

03 मौसम मोबाइल ऐप

- देश भर में बदलते मौसम और उससे जुड़ी अहम जानकारियों को लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए सरकार ने 'मौसम' नामक एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने साथ मिलकर यह ऐप तैयार किया है।
- यह मोबाइल ऐप आम लोगों को समर्पित है और इसकी रूपरेखा बिना तकनीकी जंजालों के सरल तरीके से मौसम की सूचना एवं पूर्वानुमान को प्रेषित करने के लिए तैयार की गई है। यूजर मौसम, पूर्वानुमान, राडार छवियों को एक्सेस कर सकते हैं और निकट की मौसम घटनाओं के बारे में समय रहते चेतावनियां प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल ऐप 'मौसम' की पांच सेवाएं हैं:

- **वर्तमान मौसम:** 200 शहरों के लिए रोजाना आठ घंटों पर वर्तमान तापमान, आर्द्रता, हवा की गति एवं दिशा का अद्यतन किया जाता है। सूर्योदय/सूर्यास्त एवं चांद के निकलने तथा अस्त होने के बारे में भी जानकारी दी जाती है।
- **नाऊकास्ट:** आईएमडी के राज्य मौसम विज्ञान विभाग केंद्रों द्वारा भारत के 800 स्टेशनों एवं जिलों के बारे में स्थानीय मौसम की अवधारणा की तीन घंटे पर चेतावनी जारी की जाती है। उग्र मौसम के मामले में इसके प्रभाव को भी चेतावनी में शामिल किया जाता है।
- **नगर पूर्वानुमान:** भारत के लगभग 450 शहरों के आसपास की मौसम स्थितियों के पिछले 24 घंटों एवं 7 दिनों का पूर्वानुमान।

- **चेतावनी:** नागरिकों को आने वाले खतरनाक मौसम की चेतावनी देने के लिए कलर कोड (रेड, औरेंज एवं येलो) में अगले पांच दिनों के लिए सभी जिलों के बारे में रोजाना दो बार अलर्ट जारी किए जाते हैं। कलर कोड रेड सर्वाधिक उग्र वर्ग है जो प्राधिकारियों और आम लोगों को कदम उठाने के लिए आग्रह करता है, औरेंज कोड प्राधिकारियों और आम लोगों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है जबकि येलो कोड प्राधिकारियों और आम लोगों को खुद को अपडेट रखने के लिए प्रेरित करता है।
- **राडार उत्पाद:** नवीनतम स्टेशनवार राडार उत्पादों का प्रत्येक 10 मिनट पर अद्यतन किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि अभी तक देश में मौसम पूर्वानुमान को लेकर रोजाना के अपडेट के लिए कोई खास तंत्र नही था। ऐसे में लोगों को प्राइवेट संस्थानों की रिपोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें हर एक शहर के मौसम की अपडेट नहीं होती थी। ऐसे में मौसम ऐप से इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है।

04 मोबाइल ऐप्स बीआईएस-केयर

- केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने उपभोक्ताओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप्स 'बीआईएस-केयर' और www.manakonline.in पर ई-बीआईएस के तीन पोर्टलों- मानकीकरण, अनुरूपता आकलन तथा प्रशिक्षण को लॉन्च किया।
- मोबाइल ऐप्स बीआईएस-केयर को किसी भी एंड्रायड फोन पर आपरेट किया जा सकता है। यह ऐप हिन्दी तथा अंग्रेजी में संचालन में है तथा इसे गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग करके आईएसआई चिन्हित एवं हॉलमार्क्ड उत्पादों की प्रमाणिकता की जांच कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- विदित हो कि बीआईएस की कार्यप्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू मानकों का कार्यान्वयन लागू करने के लिए प्रमाणन तथा निगरानी है। ई-बीआईएस, जो इसके सभी कार्यों, फैक्टरी एवं बाजार निगरानी तथा मोबाइल आधारित एवं एआई-सक्षम निगरानी पद्धतियों के विकास के लिए बाहर की एजेन्सियों की सेवाओं को सूचीबद्ध करने वाला एक समेकित पोर्टल है, के कार्यान्वयन द्वारा प्रवर्तन की अपनी क्षमता को सुदृढ़ कर रहा है। आयोग मंत्रालय के अनुसार यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता मानकों एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के बारे में अवगत हों तथा घटिया उत्पादों की आपूर्ति को खत्म करने के हमारे प्रयासों का एक हिस्सा बनें। मंत्रालय ने यह जानकारी भी दी कि बीआईएस उपभोक्ता भागीदारी पर एक पोर्टल का विकास कर रहा है जो उपभोक्ता समूहों के ऑनलाइन पंजीकरण, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और उसके बाद अनुमोदन तथा शिकायत प्रबंधन को सुगम बनायेगा।

- मंत्रालय के अनुसार बीआईएस ने सक्रियतापूर्वक विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के साथ करार किया है जिससे कि उन्हें 368 उत्पादों के लिए क्यूसीओ जारी करने में मदद की जा सके और 239 उत्पादों के लिए क्यूसीओ का निर्माण का कार्य प्रगति पर है। मानकों के अनिवार्य बन जाने के बाद घरेलू तथा विदेशी दोनों ही विनिर्माताओं को उनका अनुपालन करना हागा। उसके अनुसार वर्तमान में बीआईएस द्वारा जारी लाइसेंस की संख्या लगभग 37000 है जिसमें क्यूसीएस के कारण तेज बढोतरी होने की उम्मीद है।
- मंत्रालय के अनुसार प्रत्येक ई-कॉमर्स संस्था को एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने और एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है जिसका नाम, पदनाम, संपर्क विवरण उस मंच पर प्रदर्शित होना आवश्यक है। ई-कॉमर्स संस्थाओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका शिकायत अधिकारी 48 घंटों के भीतर किसी भी उपभोक्ता की शिकायत को स्वीकार कर ले और शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर उस शिकायत का निवारण कर दे।
- मंत्रालय के अनुसार इन नियमों के उल्लंघन को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत निपटा जाएगा। अनुचित व्यापार व्यवहार और भ्रामक विज्ञापनों को लेकर मुकदमे की स्थिति में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कार्रवाई कर सकता है। किसी भी मुआवजे के लिए कोई उपभोक्ता उचित अधिकार क्षेत्र के उपभोक्ता आयोग से संपर्क कर सकता है।

05 कुम्हार सशक्तिकरण योजना

- हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने वंचित कुम्हार समुदाय के सशक्तिकरण और उसे 'आत्म निर्भर भारत' अभियान से जोड़ने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा चलाई जा रही 'कुम्हार सशक्तिकरण योजना' के तहत एक सौ प्रशिक्षित कारीगरों को 100 विद्युत चाक वितरित किए।
- देश भर में अब तक 17,000 से अधिक इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए जा चुके हैं, जिससे कुम्हार समुदाय के लगभग 70,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। इलेक्ट्रिक चाक ने कुम्हारों के जीवन में बड़े स्तर पर बदलाव लाया है। इलेक्ट्रिक चाकों के साथ मिट्टी की वस्तुओं का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। वर्तमान में, देश भर में हर दिन लगभग 2 करोड़ कुल्हड़ बनाए जाते हैं। उनके अनुसार कुम्हार इन कुल्हड़ों को 400 रेलवे स्टेशनों पर सफलतापूर्वक बेच रहे हैं जो उनके लिए एक आदर्श विपणन मंच है।
- यहां यह ध्यान देने की बात है कि गुजरात के कई क्षेत्र विशेष रूप से कच्छ और सौराष्ट्र मिट्टी के पारंपरिक बर्तनों की कला के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्ष 2018 में कुम्हार सशक्तिकरण योजना के शुभारंभ के बाद से केवीआईसी ने गुजरात के विभिन्न गांवों से लगभग 750 कुम्हारों को प्रशिक्षित किया है। मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में प्रशिक्षण देने के अलावा केवीआईसी ने उन्हें इलेक्ट्रिक चाक दिए और मिट्टी मिलाने के लिए ब्लन्जर मशीन (अनुमिश्रक) जैसे अन्य उपकरण भी वितरित किए हैं। इसके परिणामस्वरूप कुम्हारों के उत्पादन और आय में 3-4 गुना वृद्धि हुई है। गुजरात के गांधीनगर जिले में केवीआईसी ने 100 कुम्हारों को प्रशिक्षित किया है और उनके बीच 100 इलेक्ट्रिक चाक और 10 ब्लन्जर मशीनें वितरित की हैं। कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत कुम्हारों की औसत आय लगभग 3000 रुपये प्रति माह से बढ़कर लगभग 10,000 रुपये प्रति माह हो गई है।

06 ग्रीन एजी परियोजना

- केंद्र सरकार ने 28 जुलाई को मिजोरम में ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत कर की। यह परियोजना कृषि क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के मकसद से शुरू की गई है। मिजोरम उन पांच राज्यों में शामिल है, जहां परियोजना लागू की जानी है। मिजोरम के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड इस परियोजना का हिस्सा हैं। इस परियोजना के तहत पांच लैंडस्कैप में 1.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि आएगी। लक्ष्य के मुताबिक, कम से कम 1,04,070 हेक्टेयर कृषि भूमि टिकाऊ विकास और जल प्रबंधन के लिए विकसित की जाएगी। उम्मीद है कि कृषि की सतत विकास की पद्धतियों से 49 मिलियन कार्बन डाईऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन कम होगा।

- ग्रीन एजी परियोजना को ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) पर इस परियोजना को क्रियान्वित कराने की जिम्मेदारी है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी इसे लागू करने में अहम भूमिका निभाएंगे। यह पायलट प्रोजेक्ट 31 मार्च 2026 को खत्म होगा। मिजोरम के दो जिलों- लुंगलेई और मामित में 1,45,670 हेक्टेयर भूमि इसके दायरे में आएगी। दो संरक्षित क्षेत्रों- डंपा टाइगर रिजर्व और थोरंगलांग वन्यजीव अभयारण्य सहित कुल 35 गांव इसके तहत कवर करने का लक्ष्य है।

- यह परियोजना भारतीय कृषि में मुख्यधारा की जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों और प्रथाओं की तलाश करती है। परियोजना का समग्र उद्देश्य राष्ट्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय लाभों की उपलब्धि और महत्वपूर्ण जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए भारत के कृषि क्षेत्र के परिवर्तनकारी परिवर्तन को उत्प्रेरित करना है। यह परियोजना भारत की कृषि और पर्यावरणीय क्षेत्र की प्राथमिकताओं और निवेशों के बीच सामंजस्य स्थापित करेगी। ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और अपने भोजन और पोषण सुरक्षा को पूरा करने की भारत की क्षमता से समझौता किए बिना राष्ट्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय लाभों की उपलब्धि को पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है।

07 तिलारी संरक्षण रिजर्व

- हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित डोडामर्ग वन क्षेत्र के लगभग 29.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 'तिलारी संरक्षण रिजर्व' (Tillari Conservation Reserve) घोषित किया है। यह राज्य का सातवाँ वन्यजीव गलियारा है जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। यह वन्य क्षेत्र महाराष्ट्र में राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य तथा गोवा के महादेई अभयारण्य को कर्नाटक के भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ता है। एक गलियारे के रूप में तीन राज्यों (गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र) के मध्य, बाघों और हाथियों के अलावा इसे कई प्रकार के हिरणों, बाइसन, बंदरों, जंगली सूअरों आदि के लिये भी एक विशिष्ट निवास स्थल के रूप में जाना जाता है। इसमें अर्द्ध-सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और कई अद्वितीय वृक्ष, तितलियाँ और फूल पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में 62 संरक्षण रिजर्व हैं, जिनमें से 13 पश्चिमी घाट में हैं। तिलारी संरक्षण रिजर्व पश्चिमी घाट में अवस्थित है। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2019 तक, भारत में 88 संरक्षण रिजर्व और 127 सामुदायिक रिजर्व थे।
- संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व सामान्यत: उन संरक्षित क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं जो राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों एवं संरक्षित जंगलों के मध्य बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। यदि क्षेत्र पूर्णत: सरकार के स्वामित्व में है तो उसे संरक्षण रिजर्व और अगर निजी स्वामित्व में है तो सामुदायिक रिजर्व कहा जाता है। सामुदायिक रिजर्व क्षेत्रों को पहली बार वर्ष 2002 के वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था।

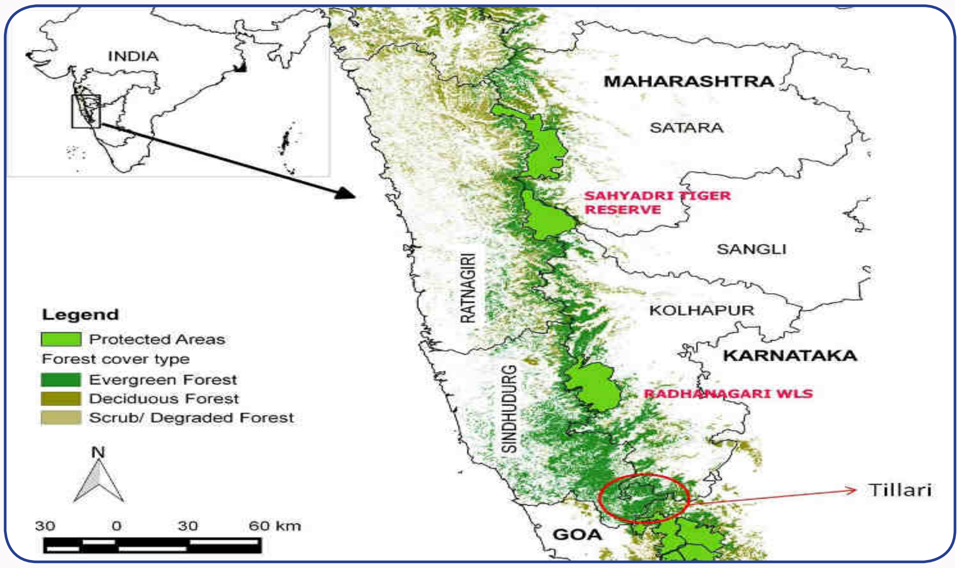

संरक्षित क्षेत्र

- संरक्षित क्षेत्रों वे क्षेत्र हैं जिनमें मानव के रहने या कम से कम संसाधनों का शोषण सीमित है। कई तरह के संरक्षित क्षेत्र हैं, जो प्रत्येक देश के सक्षम कानूनों या अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नियमों के आधार पर सुरक्षा के स्तर के हिसाब से भिन्न होते हैं। शब्द 'संरक्षित क्षेत्र' में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जिसमें सीमाएं शामिल हैं, जिनमें से कुछ समुद्र के क्षेत्र और ट्रांसबाउंडरी संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं जो कई देशों को ओवरलैप करते हैं जो संरक्षण और आर्थिक उद्देश्यों के लिए देशों की सीमा क्षेत्र से निकाले जाते हैं। ओवरलैप से अभिप्राय है कि अगर उस संरक्षित क्षेत्र में किसी देश की सीमा आती है तो उसे केवल संरक्षित क्षेत्र ही माना जायेगा बजाय उसे उस देश की सीमा मानने के।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

01
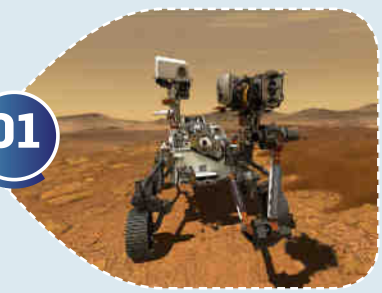

05

07

01 हाल ही में नासा ने मंगल मिशन 'मार्स 2020' लॉन्च किया। मार्स 2020 की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करें।

02 हाल ही में NGT ने भूजल के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी है। देश में भूजल की स्थिति तथा उसके संरक्षण में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करें।

03 दल-बदल विरोधी अधिनियम अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल रहा है? टिप्पणी करें।

04 डेटा सुरक्षा को लेकर लोगों में असंतोष बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे डिजिटलीकरण बढ़ रहा है वैसे-वैसे डेटा चोरी की घटनायें भी बढ़ रही हैं। डेटा चोरी की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रयासों की चर्चा करें।

05 भारत के शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए 'टेक स्टार्टअप प्रोग्राम' शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम शिक्षा व्यवस्था के बदलाव में किस प्रकार सहायक है? विश्लेषण करें।

06 "मानवीय मूल्यों में तेज गिरावट न सिर्फ मानव बल्कि प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक है।" वर्तमान संदर्भ में इस कथन की सार्थकता पर विचार कीजिए।

07 राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 2020 के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 हाल ही में किस देश ने 'इस्तांबुल कन्वेंशन' से अलग होने का निर्णय लिया है?

पोलैंड

02 भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी में अमोनिया की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए?

0.5 ppm

03 बर्न्ट शुगर (Burnt Sugar) किसकी रचना है?

अवनी दोशी

04 ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएसआईआर और विज्ञान भारती के साथ किस संस्था ने उन्नत भारत अभियान शुरू किया है?

आईआईटी दिल्ली

05 नई शिक्षा नीति, 2020 के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?

के. कस्तूरीरंगन

06 राफेल विमान भारत पहुँचने से पहले किस देश में ठहराव लिया था?

यू.ए.ई.

07 किस एशियाई देश ने कोरोना वायरस के प्रसार के बीच सभी वन्यजीवों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है?

वियतनाम

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

01

03

05

01 लोकतंत्र में एक नागरिक की भूमिका उसके वोट डालने के साथ ही समाप्त नहीं हो जाती है।

बराक ओबामा

02 इन्सान बनें, केवल नाम से ही नहीं, रूप से नहीं, शक्ल से नहीं बल्कि बुद्धि से, हृदय से, ज्ञान से।

अटल बिहारी वाजपेयी

03 सबसे महान जीत प्रेम की होती है, यह हमेशा के लिए दिल जीत लेती है।

सम्राट अशोक

04 कोई भी देश, कोई भी समाज या फिर कोई भी समुदाय अपना सर ऊँचा नहीं रख सकता यदि वहाँ महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता हो।

मनमोहन सिंह

05 मै ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रा, समानता और भाईचारा सिखाता है।

चंद्रशेखर आजाद

06 जो स्वयं सुंदर है, उसकी सुन्दरता किसी अन्य वस्तु से नहीं बढती।

कालिदास

07 जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता।

गौतम बुद्ध

ध्येयIAS
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

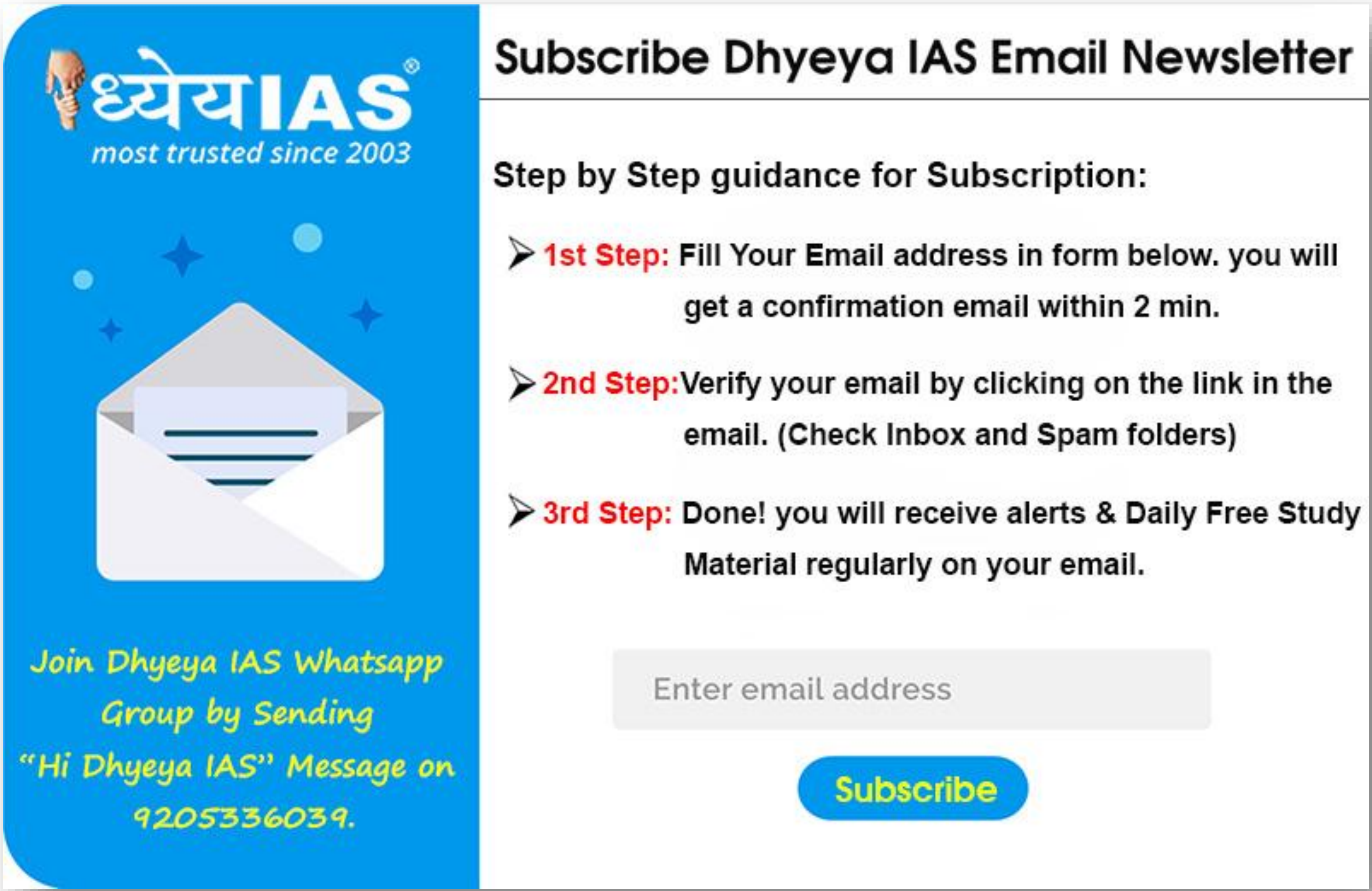

ध्येय IAS
most trusted since 2003
Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002
9506256789

Whatsapp:
9205274741

Visit:
dhyeyaias.com